20 फरवरी, संयुक्तांक (जनवरी-फरवरी) 2024 * वर्ष 33, पृष्ठ संख्या 60, अंक 01-02

राजस्थान सुजस

विशेष आलेख : राष्ट्रीय अस्मिता के पुनरुत्थान की प्राण-प्रतिष्ठा, पृष्ठ 30

विकसित राजस्थान के संकल्प को समर्पित

बजट 2024-25, लेखानुदान

सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास
सबका प्रयास, सबका कल्याण

पारंपरिक आदिवासी नृत्य दांगड़ी

दांगड़ी नृत्य दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा जिले एवं आसपास के जनजाति अंचल का प्रसिद्ध नृत्य है। इसमें आदिवासी महिलायें पारंपरिक वेशभूषा धारण कर हाथों में झांझरी लेकर एवं पुरुष ढोल के साथ नृत्य प्रस्तुत करते हैं।

हाल ही राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की बसंत पंचमी के मौके पर डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम यात्रा के दौरान पारंपरिक वाद्ययंत्रों ढोल, कुंडी व थाली की स्वर लहरियों पर पीले परिधानों में सजे लोक कलाकारों ने दांगड़ी नृत्य प्रस्तुत कर राष्ट्रपति महोदया का पारंपरिक अन्दाज में स्वागत किया।

आलेख एवं छाया - **पदम सैनी**

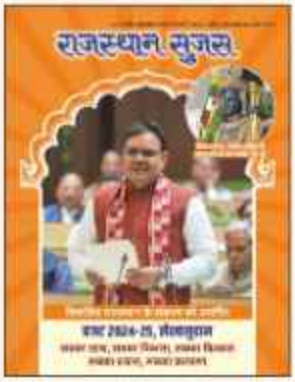

प्रधान संपादक
सुनील शर्मा

संपादक
अलका सक्सेना

सह-संपादक
डॉ. रजनीश शर्मा

उप-संपादक
आशुराज आनंद

सहायक संपादक
मोहित जैन

आवरण छाया
पदम सैनी

राजस्थान सुजस में प्रकाशित सामग्री में व्यक्त विचार लेखकों के अपने एवं आंकड़े परिवर्तनशील हैं। आवश्यक नहीं कि शासन उनसे सहमत हो। सुजस में प्रकाशित सामग्री का विभाग किसी भी रूप में उपयोग कर सकेगा।

ग्राफिक डिजाइनिंग
कृष्णा प्रिंटर्स

सम्पर्क
सम्पादक
राजस्थान सुजस (मासिक)
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
सचिवालय, जयपुर-302005
मो. नं. 94136-24352
82098-86614
e-mail :
editorsujas@gmail.com
publication.dipr@rajasthan.gov.in
Website :
www.dipr.rajasthan.gov.in

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान का मासिक

वर्ष : 33 अंक 01-02 | जनवरी-फरवरी, संयुक्तांक 2024

इस अंक में

लोक जीवन	02
संपादकीय	04
डीजीपी कॉन्फ्रेंस	10
नवनिर्वाचित विधायक ...	14
मंत्री परिषद प्रथम बैठक	26
अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा	32
ऊंट महोत्सव	38
स्वच्छ जल का संकल्प	39
स्वस्थ भारत की संकल्पना	43
सौर ऊर्जा से रोशन ...	44
मजबूत सड़क नेटवर्क ...	46
पीएम श्री विद्यालय	50
सशक्त महिला, सशक्त प्रदेश	52
नववर्ष का उपहार ...	54
आकर्षण बने ड्रोन	55
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना...	56
क्षुधाहारी, भोजन गुणकारी	58
धरोहर	59

राजस्थान हर क्षण गतिमान

05

राजभवन में हुआ शपथ ग्रहण समारोह

08

बजट 2024-25 (लेखानुदान)

15

भारत-फ्रांस मैत्री

12-13

स्टोन मार्ट 2024

25

75वां गणतन्त्र दिवस

28

21 जिलों की प्यास बुझाएगी...

42

राजस्थान सुजस के आगामी अंक के लिए मौलिक, अप्रकाशित सामग्री भिजवाएं। कृपया अपने आलेख एवं फोटोग्राफ सम्पादक को e-mail : editorsujas@gmail.com पर अथवा डाक से भेजें। पाठकगण के महत्वपूर्ण सुझाव एवं प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं।

वर्ष की मजबूत शुरुआत

वर्ष 2024 के आरम्भ के साथ ही विकास के नए युग का प्रारम्भ हो चुका है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ दिसम्बर-जनवरी में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में प्रदेश देशभर में अव्वल स्थान पर रहा। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में इस यात्रा ने 26 जनवरी तक प्रदेश के हजारों गांव-ढाणियों, शहर-कस्बों में जीवन को खुशहाल बनाने के लिए व्यापक स्तर पर जनकल्याणकारी योजनाओं से लोगों को जोड़ा।

पिछले दो माह के भीतर ही केन्द्र सरकार के सहयोग के साथ ईआरसीपी, पीकेसी लिंकेज परियोजना, जयपुर रिंग रोड के शेष निर्माण, शेखावाटी अंचल में यमुना जल के लिए तीन राज्यों में समझौते सहित वर्षों से लम्बित योजनाओं को अमली जामा पहनाने की शुरुआत हुई। साथ ही हर सेक्टर में विभिन्न निर्माण परियोजनाएं प्रारम्भ की गई हैं।

राज्य सरकार द्वारा आरम्भ से ही लिए गए जनकल्याणकारी ठोस निर्णय और जबावदेह प्रशासन का रेखांकन लोकसमर्पित राज्य के दिशा संकेतक हैं। फरवरी माह में प्रस्तुत बजट 2024-25 लेखानुदान भी विकास और जनकल्याण की इसी भावना से ओतप्रोत रहा जिसमें युवा, महिला, विद्यार्थी, किसान, कर्मचारी, उद्यमी, सभी वर्गों को साथ लेकर "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास एवं सबका कल्याण को प्रधानता दी गई।

500 वर्ष से चल रहा कोहरा भी छंटा जब रामजन्म भूमि पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प से अयोध्या में सूर्यवंशी रामलला की मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा हुई। इस नवयुगारम्भ से अयोध्या ही नहीं, सम्पूर्ण देश और विश्व में राष्ट्रवाद, समरसता और आस्था का नया सूर्योदय हुआ।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष श्री इमानुएल मैक्रों की जयपुर यात्रा ने विश्वभर का ध्यान फिर एक बार जयपुर और राजस्थान की हेरिटेज की ओर खींचकर भारत-फ्रांस की नई मैत्री और पर्यटन संभावनाओं को और सींचा। इस वर्ष अपनी पहली यात्रा में प्रधानमंत्री पुलिस महानिदेशकों एवं महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में नए आपराधिक कानूनों में नागरिक, गरिमा और न्याय पहले का संदेश देकर गए। इस संदेश की भावना ही आगामी दिनों में देश में विधि के शासन के नए अध्याय का आरम्भ है।

नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ प्रदेश और देश के विकास संकल्प, विभिन्न उपलब्धियों और घटनाचक्र को समेकित करता जनवरी माह का यह अंक आप सुधि पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है।

(सुनील शर्मा)
प्रधान सम्पादक

विकसित भारत संकल्प यात्रा

राजस्थान हर क्षण गतिमान

▪ आशुराज आनंद
जनसम्पर्क अधिकारी

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में 16 दिसम्बर 2023 से प्रारम्भ हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा ने लगभग 11 हजार 209 ग्राम पंचायतों एवं 918 नगरीय निकायों में लगभग 58 फीसदी से अधिक लोगों यानी लगभग 4 करोड़ से अधिक प्रदेश वासियों को इस संकल्प का हिस्सा बनाया। यह संकल्प यात्रा लाखों लोगों को केन्द्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की वजह बनी। सरकारी विभागों की तमाम लोक कल्याणकारी योजनाओं का सरकारी लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने की सुनिश्चितता पर केन्द्रित विकसित भारत संकल्प यात्रा का उत्साह प्रदेशवासियों में देखते ही बना। यह यात्रा एक ऐसा माध्यम बनी, जिसने महिला, युवा, किसान, गरीब सहित सभी वर्गों का समर्थन हासिल किया। प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने स्वयं इस अभियान की कमान संभाली और लगातार मॉनिटरिंग के साथ ही विभिन्न जिलों में यात्रा के दौरान लगाए गए शिविरों में शामिल हुए।

विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश के साथ ही समग्र भारत देश के लिए समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से समृद्धि की ओर कूच करने की अनूठी यात्रा सिद्ध हुई।

विकास पथ पर सबको एकसाथ लेकर चलने के संकल्प की यात्रा के रूप में इसके माध्यम से सरकार ने नागरिकों की जरूरतों की पहचान की और हर हकदार को उसका अधिकार देने का साझा और सकारात्मक प्रयास किया। ताकि हर अंतिम वंचित पात्र लाभार्थी तक सरकार की कल्याणकारी भावना और अप्रोच का लाभ मिल सके। साथ ही केन्द्र व प्रदेश सरकार मिलकर अपनी योजनाओं को अंतिम छोर तक व्यापक पैमाने पर आमजन के बीच पहुंचा सके।

चार अमृत स्तम्भ

विकसित भारत का संकल्प 4 अमृत स्तम्भों पर पूरी मजबूती के साथ टिका है। यह अमृत स्तम्भ हैं- नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान भाई-बहन और गरीब परिवार। इन चार स्तम्भों के उत्थान से ही भारत को विकसित भारत बनाया जाना संभव हो सकता है।

विकसित भारत संकल्प यात्रा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की संतृप्ति प्राप्त करने के लिए विस्तारित गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने का यह एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। इसे देशभर में सभी ग्राम पंचायतों, नगरीय, स्थानीय एवं शहरी निकायों में शामिल किया गया। इसके लक्ष्य हैं...

1. यह अभियान कमजोर लोगों तक सेवाओं एवं योजनाओं की पहुंच प्रदान करता है, जो विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र तो हैं लेकिन जिन्होंने इसका अभी तक लाभ नहीं उठाया है।
2. जानकारी उपलब्ध करवाना, प्रौद्योगिकी की पहुंच और योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आउटरीच।
3. व्यक्तिगत आख्यानों और अनुभवों को साझा करने के माध्यम से सरकारी योजनाओं से लाभान्वितों का प्रत्यक्ष जुड़ाव।
4. विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान विवरण के माध्यम से संभावित लाभार्थियों का नामांकन करना।

राज्य से राष्ट्र विकास का सेतु

राजस्थान में विकसित भारत संकल्प यात्रा को प्रदेश के विकास से राष्ट्र के विकास की संकल्पना को साकार करने के अमृत सेतु की तरह देखा गया है। सरल शब्दों में कहें तो यह संकल्प है...

- प्रदेश के हर घर को जल कनेक्शन से जोड़ने का
- महिलाओं और बच्चों का आज और कल सुरक्षित करने का
- प्रत्येक प्रदेशवासी के हाथ को काम देने का
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करने का
- राजस्थान में रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी जैसे कॉरिडॉर की सोच को आकार देकर ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का
- जनजातीय समुदाय को समुचित मान-सम्मान, अवसर और अधिकार देने का
- अवसंरचना के निर्माण और नव-निर्माण का
- वंचितों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का

इसी तरह **यह संकल्प है-** विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य कवरेज की योजना आयुष्मान भारत के माध्यम से सर्वे सन्तु निरामयाः का स्वप्न साकार करने का, पी.एम. उज्ज्वला, मुद्रा, सुकन्या समृद्धि और सही पोषण देश रोशन के भाव को आत्मसात कर आत्मनिर्भर नारी बनाने का। यह संकल्प है-किसानों के कल्याण को सुनिश्चित करने का। पी.एम. गरीब कल्याण अन्न योजना से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का। **यह संकल्प है-** ऐतिहासिक स्थलों के जीर्णोद्धार एवं स्वदेश दर्शन योजना थीम आधारित पर्यटक सर्किट विकास एवं राजस्थान डेजर्ट सर्किट के माध्यम से आध्यात्मिक स्थलों के संरक्षण, संवर्धन एवं उन्नयन का। **यह संकल्प है-** स्टार्ट अप इण्डिया के द्वारा नवाचार, इन्क्यूबेशन और प्रोत्साहन से उद्यमिता के मनोभाव को बढ़ावा देने का। **यह संकल्प है-** आत्मनिर्भर भारत के विकास इंजन को गति देने के लिए राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे स्टेशनों और रीजनल कनेक्टिविटी के नए युग की शुरुआत का।

गरीबों की सेवा व वंचितों का सम्मान, किसानों के कल्याण की सुनिश्चितता, नारी शक्ति एवं महिलाओं के नेतृत्व का विकास, भारत की अमृत पीढ़ी का सशक्तिकरण, मध्यम वर्ग के लिए सरल जीवन, सभी के लिए सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा, "राष्ट्र प्रथम" विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा में आधुनिकीकरण के साथ गुणवत्तात्मक उत्थान, भारत को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में सार्थक प्रयास, व्यापार की वैश्विक सुगमता और आयात निर्यात को बढ़ावा, सुदृढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं प्रगति पथों का निर्माण, भारत के टेक्नोलॉजी युग का नवसूत्रपात, नॉर्थ ईस्ट के विकास के नए इंजन से विकास की गति को और प्रगति प्रदान करने के साथ-साथ विरासत और विकास के पर्यावरणीय पहलुओं को केन्द्र बिन्दु में रखकर सतत, पोषणीय अथवा धारणीय विकास की अवधारणा को बल देने जैसे उद्देश्य से संचालित विकसित भारत संकल्प यात्रा निश्चित रूप से भारत को नई ऊंचाइयों पर आसीन करने की यात्रा में एक बड़ा पड़ाव है।

विकसित भारत संकल्प यात्रा

विकसित भारत संकल्प यात्रा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में राजस्थान प्रथम

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राजस्थान में 16 दिसम्बर 2023 को प्रारंभ की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा का समापन 26 जनवरी 2024 को हुआ। इस यात्रा को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई में भरपूर जनसमर्थन मिला। **प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा की कमान स्वयं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अपने हाथों में ली। उन्होंने प्रदेशभर में यात्रा शिविरों का दौरा करके प्रत्येक प्रदेशवासी तक सरकार की योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया।** यात्रा के माध्यम से प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों को भारत सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभों के बारे में अवगत करवाया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा लॉन्च होने के समय विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के कारण राजस्थान उसका हिस्सा नहीं बन पाया था उसके उपरांत भी यात्रा शिविरों को लेकर राजस्थान कई मामलों में देशभर में अव्वल है। शिविरों में संचालित 18 योजनाओं में से 14 योजनाओं में राजस्थान ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जिनमें आमजन की उपस्थिति, जनप्रतिनिधियों की भागीदारी, हेल्थ चैकअप कैम्प, आयुष्मान भारत कार्ड ई-केवाईसी, टीबी जांच, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पुरस्कार वितरण, शपथ या संकल्प ऑफलाइन, ऑनलाइन, सोयल हेल्थ कार्ड, नेचुरल फार्मिंग, किसान क्रेडिट कार्ड, मेरी कहानी-मेरी जुबानी एवं धरती कहे पुकार के योजनायें शामिल हैं।

शिविरों में पीएम उज्ज्वला योजना में 7 लाख 95 हजार पंजीकरण, 15 लाख 31 हजार से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ, स्वास्थ्य कैंपों में 2 करोड़ 89 लाख लोगों की जांच, आयुष्मान भारत कार्ड ई-केवाईसी में 95 लाख से अधिक पंजीकरणों और 2 करोड़ 22 लाख लोगों की टीबी जांचों के साथ राजस्थान पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है। इसके साथ ही 80 लाख से अधिक मेरी कहानी-मेरी जुबानी लाभार्थी, संकल्प या शपथ (ऑफलाइन व ऑनलाइन) में 3 करोड़ 39 लाख, सोयल हेल्थ कार्ड में 11 हजार 209, नेचुरल फार्मिंग में 11 हजार 209 एवं धरती कहे पुकार के योजना में 11 हजार 209 पात्र व्यक्तियों के साथ राजस्थान प्रथम स्थान पर है।

यात्रा के दौरान राजस्थान में कुल 12 हजार 127 शिविर आयोजित किए गए जिनमें कुल 3 करोड़ 78 लाख प्रतिभागी प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हुए। इनमें 432 शिविरों में सांसदों एवं 1हजार 663 शिविरों में विधायकों की भागीदारी रही। यात्रा के व्यापक प्रचार- प्रसार एवं आमजन को यात्रा के प्रति जागरूक करने के लिए शिविरों में वैन भी भेजी गई। इस वैन के द्वारा कैलेंडर, ब्रोशर, बुकलेट, क्विज विजेताओं के लिए टी-शर्ट एवं कैप उपलब्ध करवाये गए।

मेरी कहानी-मेरी जुबानी

धुएं की समस्या से मिली निजात

रोजाना चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियों के इंतजाम, कभी भीगी लकड़ियों के कारण तो कभी गली हुए लकड़ियों के कारण धुएं की समस्या का सामना करना पड़ता था। अब गैस कनेक्शन मिलने से रोजाना की धुएं की समस्या से निजात मिलने के साथ परिवार को अब गर्म भोजन किसी भी समय उपलब्ध हो सकेगा। **श्रीमती मीरा,** अटारी गांव

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का मिला लाभ

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि राशि के साथ ही मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का भी लाभ मिल रहा है, कृषि अधिकारियों की सिफारिश से फसलों में उर्वरकों का उपयोग कर रहा हूं। बचत के साथ ही जमीन का उपजाऊपन भी खराब होने से बच रहा है।

श्री प्रहलाद, पुरवाईखेड़ा, बयाना

शौच के लिए बाहर जाने से मुक्ति

स्वच्छ भारत मिशन योजना से शौचालय निर्माण के लिए अनुदान मिला जिससे अब बाहर जंगल में शौच जाने से निजात मिली है। पूरे परिवार को अब बाहर शौच के लिए नहीं जाना पड़ता। साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ भी मिल रहा है।

श्री प्रभाती जाटव, ग्राम पंचायत गौगेरा, भुसावर

अब नहीं टपकती घर की छत

प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने से पहले मैं कच्ची झोपड़ी में रहती थी। जिससे सर्दी, गर्मी एवं वर्षा हर मौसम में परेशानी का सामना करना पड़ता था। बरसात में छत से पानी टपकता था। अब मेरा परिवार हर मौसम में सुरक्षा के साथ निवास करता है।

श्री लक्ष्मीबाई, पंचायत समिति भुसावर

राजभवन में हुआ शपथ ग्रहण समारोह

12 कैबिनेट एवं 9 राज्य मंत्री

माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने 30 दिसंबर 2023 को राजभवन में आयोजित भव्य समारोह में 12 कैबिनेट, 5 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं 5 राज्य मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। सभी सदस्यों ने हिंदी भाषा में ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ ली। श्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी के पद से इस्तीफ़ा देने के बाद अब राज्य सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या 24 है। माननीय राजपाल महोदय ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के परामर्श से 5 जनवरी 2024 को प्रत्येक मंत्री को उनके विभागों का कार्यभार सौंप दिया है एवं विभागों का बंटवारा इस प्रकार से किया गया है -

श्री भजन लाल शर्मा, मुख्यमंत्री

कार्मिक, आबकारी, गृह, सामान्य प्रशासन, नीति निर्धारण प्रकोष्ठ - मुख्यमत्री सचिवालय, सूचना एवं जनसंम्पर्क विभाग भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी)

सुश्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री

वित्त, पर्यटन, कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व, सार्वजनिक निर्माण, महिला एवं बाल विकास, बाल अधिकारिता विभाग

डॉ. प्रेमचन्द बैरवा, उप मुख्यमंत्री

तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष) परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

कैबिनेट

श्री किरोड़ी लाल
कृषि एवं उद्यानिकी, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा, जन अभियोग निराकरण विभाग

श्री गजेन्द्र सिंह
चिकित्सा और स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं (ईएसआई)

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़
उद्योग एवं वाणिज्य, सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार, युवा मामले और खेल, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता, सैनिक कल्याण विभाग

श्री मदन दिलावर
विद्यालयी शिक्षा (स्कूल एजूकेशन), पंचायती राज, संस्कृत शिक्षा विभाग

श्री कन्हैयालाल
जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, भू-जल विभाग

श्री जोगाराम पटेल
संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य और विधि परामर्शी कार्यालय, न्याय विभाग

श्री सुरेश सिंह रावत
जल संसाधन, जल संसाधन (आयोजना) विभाग

श्री अविनाश गहलोत
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

श्री सुमित गोदारा
खाद्य एवं नागरिक, उपभोक्ता मामले विभाग

श्री जोराराम कुमावत
पशुपालन एवं डेयरी, गोपालन, देवस्थान विभाग

श्री बाबूलाल खराड़ी
जनजाति क्षेत्रीय विकास, गृह रक्षा विभाग

श्री हेमन्त मीणा
राजस्व, उपनिवेशन विभाग

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

श्री संजय शर्मा
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

श्री गौतम कुमार
सहकारिता, नागरिक उड्डयन विभाग

श्री झाबर सिंह खर्रा
नगरीय विकास, स्वायत्त शासन विभाग

श्री हीरालाल नागर
ऊर्जा विभाग

राज्य मंत्री

श्री ओटा राम देवासी
पंचायती राज, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

डॉ. मंजू बाघमार
सार्वजनिक निर्माण, महिला एवं बाल विकास और बाल अधिकारिता विभाग

डॉ. विजय सिंह
राजस्व, उपनिवेशन, सैनिक कल्याण विभाग

श्री कृष्ण कुमार के.के. विश्नोई
उद्योग एवं वाणिज्य, युवा मामले और खेल, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता, नीति निर्धारण विभाग

श्री जवाहरसिंह बेढम
गृह, गोपालन, पशुपालन एवं डेयरी, मत्स्य विभाग

कैबिनेट मंत्री

श्री मदन दिलावर

श्री बाबूलाल खराड़ी

श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर

श्री किरोड़ी लाल मीणा

श्री जोगाराम पटेल

श्री सुरेश सिंह रावत

श्री अविनाश गहलोत

श्री जोराराम कुमावत

श्री हेमंत मीणा

श्री कन्हैयालाल चौधरी

श्री सुमित गोदारा

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

श्री हीरालाल नागर

श्री झाबर सिंह खर्रा

श्री गौतम कुमार

श्री संजय शर्मा

राज्य मंत्री

श्री जवाहर सिंह बेढम

श्री कृष्ण कुमार विश्नोई

श्री विजय सिंह चौधरी

डॉ. मंजू बाघमार

ओटाराम देवासी

पुलिस महानिदेशकों व महानिरीक्षकों का 58वां अखिल भारतीय सम्मेलन

नए आपराधिक कानूनों में नागरिक पहले, गरिमा पहले और न्याय पहले की भावना -प्रधानमंत्री

2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए भारतीय पुलिस को खुद को आधुनिक और विश्वस्तरीय बल में बदलना चाहिए: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

▪ डॉ. गोविन्द पारीक
अति. निदेशक (से.नि.)

देशभर के पुलिस महानिदेशकों व महानिरीक्षकों के 58वें अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन 5 से 7 जनवरी 2024 तक जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सम्मेलन में शामिल होकर देश के सर्वोच्च पुलिस अधिकारियों को दिशा-निर्देश प्रदान किये। सम्मेलन में राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों की सर्वश्रेष्ठ परंपराओं को प्रस्तुत किया गया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सम्मेलन में तीन नए आपराधिक कानूनों के अधिनियमन पर चर्चा में इसे आपराधिक न्याय प्रणाली में एक आदर्श बदलाव बताया। उन्होंने रेखांकित किया कि नए आपराधिक कानून 'नागरिक पहले, गरिमा पहले और न्याय पहले' की भावना के साथ बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस को अब 'डंडा' के बजाय 'डेटा' से काम करना चाहिए। सम्मेलन में उनका संदेश था कि 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए भारतीय पुलिस को खुद को आधुनिक और विश्वस्तरीय बल में बदलना चाहिए।

श्री मोदी ने पुलिस प्रमुखों से नए अधिनियमित कानूनों के पीछे के चिंतन और भावना को समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाने के लिए कल्पनाशील ढंग से सोचने का आग्रह किया, नए कानूनों के तहत महिलाओं और लड़कियों को उनके अधिकारों और सुरक्षा के बारे में जागरूक करने पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने पुलिस से महिला सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया । ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महिलाएं निडर होकर कभी भी और कहीं भी काम कर सकें। महिलाओं को उनके अधिकारों एवं नए कानूनों के तहत उन्हें प्रदान की गई सुरक्षा के बारे में जागरूक करें।

सम्मेलन में प्रधानमंत्री के प्रमुख दिशा-निर्देश

- नागरिकों के बीच पुलिस की सकारात्मक छवि बनाएं।
- नागरिक-पुलिस संपर्क की मजबूत के लिए खेल आयोजन प्रभावी।
- सोशल मीडिया का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए।
- साइबर अपराधों और एआई की चुनौतियों के लिए पुलिसकर्मियों को समुचित प्रशिक्षण।
- अधिकारी स्थानीय आबादी के साथ बेहतर 'कनेक्शन' के लिए सीमावर्ती गांवों में पहुंचें।

गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 5 जनवरी को इस सम्मेलन का शुभारंभ किया। उद्घाटन सत्र को सम्बोधित करते हुए उन्होंने अमृत काल में सुरक्षा के आदर्श प्रतिमान स्थापित करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने वर्ष 2014 के बाद आतंकवाद और अपराध नियंत्रण के लिए किये गए कार्यों व उपलब्धियों पर प्रकाश डाला।

सम्मेलन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री निसिथ प्रमाणिक, गृह राज्य

चर्चा और चिंतन के मुख्य विषय

❖ 3 नए आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन ❖ खालिस्तान समर्थक गतिविधियां ❖ जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी हमला ❖ आम चुनाव के मुद्दे ❖ साइबर क्राइम ❖ माओवादी समस्या ❖ अंतरराज्यीय पुलिस समन्वय ❖ आतंकवाद निरोध ❖ ऑनलाइन फ्रॉड ❖ सीमा पार से आतंकवाद और वामपंथी उग्रवाद ❖ साइबर क्राइम ❖ पुलिस के लिए टेक्नोलॉजी, जेल सुधार ❖ वामपंथी, चरमपंथ और आतंक विरोधी चुनौतियां ❖ पुलिसिंग और सुरक्षा के क्षेत्र में भविष्य के मुद्दे जैसे एआई ❖ डीपफेक जैसी टेक्नोलॉजी के जरिए पैदा होने वाली चुनौतियों और उनसे निपटने के तरीकों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत कुमार डोभाल, केंद्रीय गृह सचिव अजय श्री कुमार भल्ला के साथ ही देश के सभी राज्यों के डीजीपी, पैरामिलिट्री फोर्स समेत अन्य जांच एजेंसियों के प्रमुख शामिल हुए। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक श्री उत्कल रंजन साहू ने सोशल मीडिया और जनजातीय मसलों पर अपना प्रस्तुतीकरण दिया।

❖ पुलिस आधुनिकीकरण एवं संबंधित आधारभूत संरचना के लिए 200 करोड़ रुपये का 'Police Modernisation and Infrastructure Fund' गठित किया जाएगा।

❖ नवसृजित 34 (चौंतीस) पुलिस थानों में परिवादियों की त्वरित सुनवाई तथा सहयोग हेतु Cyber Helpdesk तैयार होगी। स्थानीय प्रशासन एवं विभिन्न एजेंसियों के समन्वय से hotspot क्षेत्रों में cyber crime नियंत्रण के लिए ठोस कार्ययोजना बनेगी।

2013 के बाद प्रारम्भ हुए दिल्ली से बाहर आयोजन

वर्ष 2013 तक इन सम्मेलनों का आयोजन राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में ही किया जाता था। साल 2014 में डीजीपी सम्मेलन का आयोजन गुवाहाटी में, 2015 में कच्छ के रण, 2016 में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद, 2017 में टेकनपुर (मध्य प्रदेश), 2018 में केवडिया (गुजरात), 2019 में पुणे, 2021 में लखनऊ में और 2023 में दिल्ली में आयोजित हुआ था।

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों को मिला मंच, चुनौतियों पर मंथन

राजस्थान पुलिस साइबर हैकाथॉन 1.0

साइबर दुनिया में भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए जागरूकता एवं पुलिस की समस्याओं की तकनीकी समाधान के साथ ही युवा और प्रतिभाशाली साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों को मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस साइबर क्राइम अवेयरनेस मिशन के तहत 17 एवं 18 जनवरी 2023 को राजस्थान पुलिस साइबर हैकाथॉन 1.0 का सफल आयोजन किया गया। राज्यपाल श्री मिश्र ने साइबर अपराध शोध, विश्लेषण और अन्य महती कार्य दलों के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए।

प्रमुख गतिविधियां : राजस्थान पुलिस साइबर क्राइम अवेयरनेस मिशन व साइबर वॉलिंटियर पोर्टल लॉन्च ❖ विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के साथ पुलिस का साइबर सुरक्षा पर एमओयू ❖ पूर्व संध्या पर 16 जनवरी को पुलिस अकादमी परिसर में आकर्षक ड्रोन शो ❖पुलिस पोर्टल पर 2 महीने पहले 12 प्रॉब्लम स्टेटमेंट की चुनौती, समाधान करने वालों को वर्गवार 20 लाख रुपये तक इनाम घोषित

❖ पोर्टल पर शैक्षणिक संस्थानों, उद्योगों, रिसर्च लैबों और स्टार्टअप के 1665 प्रतिभागियों द्वारा पंजीयन। चयनित 289 टीमों के प्रतिभागियों ने समाधान हेतु 36 घंटे तक निरंतर काम किया।

❖ उद्घाटन दिवस पर 7 सत्र एवं समापन दिवस पर 10 सत्रों में पुलिस अधिकारी, साइबर एक्सपर्ट्स, मीडिया, तकनीकी संस्थानों, शिक्षण संस्थान एवं अन्य हितधारक संगठन, संस्थानों के विशेषज्ञ, प्रतिनिधियों ने साइबर सम्बन्धी विविध विषयों पर सम्बोधित किया।

साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930

भारत-फ्रांस मैत्री:

Amitié Franco-Indienne :

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष श्री इमानुएल मैक्रों 75वें गणतंत्र दिवस से पूर्व 25 जनवरी को जयपुर पहुंचे। यहां उन्होंने रोड शो कर लोगों को भारत-फ्रांस की अटूट मैत्री का संदेश दिया और जंतर-मंतर, हवामहल, आमेर महल का अवलोकन किया। रोड शो के दौरान उन्होंने हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन स्वीकार किया।

राजस्थान चैप्टर

Chapitre du Rajasthan

फ्रांस के राष्ट्रपति श्री मैक्रों ने आमेर में हस्तशिल्पियों से मुलाकात कर पारम्परिक नृत्य का आनंद लिया और शहर के बाजार में खरीददारी के साथ ही चाय की चुस्कियों के बाद यूपीआई के माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया देख अभिभूत हुए।

एक दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम

नवनिर्वाचित विधायक सदन के नियम और प्रक्रियाओं से हुए रुबरु

▪ दिनेश शर्मा
सहायक जनसम्पर्क अधिकारी

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। देश में लोकतांत्रिक परम्पराओं को कायम रखने के साथ ही इन्हें मजबूत बनाने में संसद और विधान मंडलों की अहम भूमिका रही है। ये परम्पराएं और अधिक पल्लवित हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि सदन के सदस्यों को अपने दायित्वों और कार्यों की भली प्रकार से जानकारी हो।

हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव से सदन में चुनकर पहुंचे विधायकों में से एक तिहाई से अधिक ऐसे हैं जो पहली बार सदन के सदस्य बने हैं। नवनिर्वाचित सदस्यों को सदन के नियमों, संसदीय प्रक्रियाओं और आचरण सम्बन्धी जानकारी के लिए विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी की पहल पर राज्य विधानसभा में 16 जनवरी को एक दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विधानसभा सदस्यों को विशेषज्ञों द्वारा सदन के नियम और प्रक्रियाओं की बारीकी से जानकारी दी गई। पहली बार सदन के सदस्य बने विधायकों के साथ ही पूर्व में सदन के सदस्य रह चुके विधायकों के लिए भी यह जानकारी इस मायने में अत्यन्त महत्वपूर्ण रही कि उन्हें अद्यतन जानकारियों से रूबरू होने का अवसर मिला।

इस प्रबोधन कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने सम्बोधित किया। वहीं, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला समापन सत्र के मुख्य अतिथि रहे। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने उद्घाटन और समापन सत्र की अध्यक्षता की जबकि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की इन दोनों सत्रों में गरिमामय मौजूदगी रही।

प्रबोधन कार्यक्रम में 6 सत्रों में सदन की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम तथा सदन में आचरण, संसदीय परम्पराएं, **द्वितीय सत्र में** प्रश्नकाल एवं शून्यकाल, **तृतीय सत्र में** संसदीय समितियां एवं उनकी कार्य प्रणालियां, **चतुर्थ सत्र में** संसदीय विशेषाधिकार एवं विधेयक पारण प्रक्रिया, **पंचम सत्र में** बजट प्रबंधन एवं कटौती प्रस्ताव एवं **षष्ठम सत्र में** संसदीय प्रस्ताव यथा स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव तथा विशेष उल्लेख के प्रस्ताव सहित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की जानकारी दी गई।

नव निर्वाचित सदस्यों को मंच से संदेश...

"पूरी दुनिया के लिए भारत प्रजातांत्रिक मूल्यों की दृष्टि से आदर्श राष्ट्र है। लोकतंत्र में विकास रूपी गंगा की शुरुआत विधायिका से होती है। देश को आगे बढ़ाने में सरकार और विपक्ष के साथ ही आम नागरिकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

श्री जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति

सदन में सार्थक चर्चाएं होने से ही जनता के हित में बेहतर परिणाम आएंगे। पक्ष-विपक्ष मिलकर जनता के हित में कार्य करेंगे तो ही राज्य को विकास के पथ पर अग्रसर कर पाएंगे।

श्री ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष

नवनिर्वाचित सदस्यों को सदन की प्रक्रिया, कार्य संचालन एवं आचरण सम्बन्धी नियमों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। विधायक जितना अधिक समय सदन में बिताएंगे उतना ही अधिक उन्हें सीखने को मिलेगा।

श्री वासुदेव देवनानी, विधानसभा अध्यक्ष

प्रबोधन कार्यक्रम से संसदीय पद्धति, प्रक्रिया, कार्य संचालन के नियम, अभिसमय, शिष्टाचार और परंपराओं से जुड़े विभिन्न आयामों को समझने का सुअवसर मिलेगा।

श्री भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री"

बजट 2024-25

लेखानुदान

8 फरवरी, 2024, गुरूवार

उप मुख्यमंत्री (वित्त) श्रीमती दिया कुमारी ने 8 फरवरी को राजस्थान विधान सभा में राज्य के वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक वित्तीय अनुमान प्रस्तुत किये। अपने वक्तव्य का प्रारम्भ करते हुए उन्होंने कहा, **प्रदेश को अग्रणी पंक्ति में लाने के लिए 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास व सबका कल्याण' की सोच के साथ अथक परिश्रम कर अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने के सतत प्रयास किए जाएंगे।** प्रस्तुत हैं उनके बजट वक्तव्य के सम्पादित अंश...

वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों के अनुसार राज्य पर कुल ऋण भार 5 लाख 79 हजार 781 करोड़ रुपये है और राज्य का Debt-GSDP अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों में, पंजाब के बाद सर्वाधिक है। वर्ष 2023-24 के अन्त में राज्य में प्रति व्यक्ति ऋण, वर्ष 2017-18 के 36 हजार 880 रुपये से बढ़कर, 70 हजार 800 रुपये होना सम्भावित है। राज्य में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार के सहयोग के साथ-साथ, राज्य सरकार की ठोस कार्ययोजना, सुशासन एवं कठिन परिश्रम से प्रदेश को सतत विकास मार्ग पर अग्रसर किया जाएगा। राजस्थान को विकसित, समृद्ध, सशक्त एवं खुशहाल प्रदेश बनाने के लिए किसी भी प्रकार के संसाधनों की कमी नहीं आने दी जायेगी।

शिक्षा और स्वास्थ्य भी आधारभूत आवश्यकता

बिजली, पानी और सड़क के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देकर उन्हें सर्वसुलभ किया जाये, तो रोजगार अपने आप पैदा होगा और भावी पीढ़ियों के लिए मजबूत आधार का निर्माण होगा।

450 रुपये में एलपीजी सिलेण्डर से 73 लाख परिवारों को राहत

प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटियों को लागू करने की दिशा में त्वरित गति से कार्य करना प्रारंभ कर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समस्त गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रु में LPG Cylinder देने के संकल्प को लागू कर लगभग 73 लाख परिवारों को राहत प्रदान की है।

श्रीअन्नपूर्णा रसोई में भोजन की मात्रा बढ़ी

जरूरतमंद व्यक्तियों को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने की दृष्टि से, पूर्व में दिये जा रहे 450 ग्राम भोजन की मात्रा को बढ़ाकर श्रीअन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से 600 ग्राम भोजन देने का निर्णय किया गया है। इस हेतु प्रति थाली राजकीय सहायता 17 रुपये से बढ़ाकर 22 रुपये की गयी है। इस योजना पर लगभग 350 करोड़ रुपये वार्षिक व्यय होगा।

क्षेत्रीय संतुलन के लिए 1 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान

प्रदेश के लाडपुरा, नसीराबाद, सिवाना, आहोर, डग, मालपुरा, गोगुन्दा जैसे कई इलाकों/क्षेत्रों में विकास का क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करने की दृष्टि से ऐसे वंचित विधानसभा क्षेत्रों में अतिरिक्त महाविद्यालय, विद्यालय, चिकित्सालय, प्रशासनिक कार्यालय आदि स्थापित अथवा क्रमोन्नत करने के लिए एक हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा।

राज्य सड़क निधि में 1500 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान

प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सड़कों के उन्नयन एवं निर्माण के क्षेत्रीय भेदभाव के समाधान के लिए State Road Fund में एक हजार 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जाएगा।

बिजली कम्पनियां बनेंगी अधिक प्रोफेशनल, दशक का प्लान बनेगा

वर्तमान में DISCOMs पर लगभग 88 हजार 700 करोड़ रुपये सहित समस्त बिजली कम्पनियों पर एक लाख 39 हजार 200 करोड़ रुपये से अधिक का ऋणभार है। वर्ष 2022-23 के अनुसार राजकीय उत्पादन कम्पनी की उत्पादन क्षमता लगभग 8 हजार 300 MW होने पर भी औसतन 4 हजार 800 MW अर्थात मात्र लगभग 55 प्रतिशत क्षमता के साथ उत्पादन हो रहा है। वर्ष 2022-23 में 3 हजार 700 करोड़ रुपये से अधिक की बिजली Exchange से खरीदने के कारण यह अतिरिक्त वित्तीय भार राजकोष पर पड़ा।

इस स्थिति से निपटने व बिजली कम्पनियों में Professional Administration स्थापित करने के लिए समस्त आवश्यक कदम उठाये जाएंगे। प्रसारण निगम में केन्द्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप 'Invit/ToT" लाने के साथ ही, सभी बिजली कम्पनियों/निगमों का विशेषज्ञों की सहायता से 'Business Plan' तथा 10 वर्ष की अवधि ध्यान में रखते हुए Resource Adequacy Plan बनाकर समयबद्ध रूप से लागू किया जाएगा।

5 लाख से अधिक घरों पर सोलर प्लांट से 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली

माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में प्रभु श्रीराम की मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा के पावन एवं ऐतिहासिक दिवस-22 जनवरी, 2024 को सम्पूर्ण देश में एक करोड़ households को सौर ऊर्जा से electrify करने की महत्वाकांक्षी 'प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना' की घोषणा की है। राजस्थान में Solar Insolation देश में सर्वाधिक है। ऐसी स्थिति में इस योजना का लाभ प्रदेशवासियों को अधिकाधिक प्राप्त हो, इस हेतु ऊर्जा विभाग में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का गठन कर 5 लाख से अधिक घरों पर Solar Plants स्थापित करने का लक्ष्य प्रस्तावित है। जिससे ऐसे परिवारों को प्रतिमाह 300 यूनिट तक बिजली निःशुल्क मिल सकेगी।

बड़े शहरों के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसें

पेट्रोल एवं डीजल की बचत के लिए Public Transport में Electric Vehicles को बढ़ावा देने हेतु, Inter-state के साथ-साथ जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा जैसे बड़े शहरों के लिए 500 Electric Buses उपलब्ध करवायी जाएंगी।

सीतापुरा-विद्याधर नगर जयपुर मेट्रो के लिए बनेगी डीपीआर

जयपुर शहर की Traffic Congestion सम्बन्धी समस्या का समाधान करने की दृष्टि से Jaipur Metro का विस्तार टोंक रोड के साथ सीतापुरा, अम्बाबाड़ी से होते हुए विद्याधर नगर तक के route पर करने के लिए DPR तैयार करवायी जायेगी।

25 लाख ग्रामीण परिवारों को आगामी वर्ष नल से जल

जल जीवन मिशन परियोजना का कार्य पूर्ण पारदर्शिता एवं गुणवत्ता के साथ तेजी से सम्पन्न करते हुए आगामी वर्ष 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया जायेगा। इस कार्य पर लगभग 15 हजार करोड़ रुपये व्यय प्रस्तावित है।

ERCP परियोजना River Linking Project में सम्मिलित

21 जिलों को होगा लाभ

माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन एवं माननीय केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री की पहल पर केन्द्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रदेश के 21 जिलों में पेयजल के साथ-साथ सिंचाई के लिए अति महत्वपूर्ण ERCP परियोजना (Eastern Region Canal Project) को River Linking Project में सम्मिलित कर स्वीकृत किया गया है। इसके लिए राज्य एवं केन्द्र सरकार के मध्य MOU को sign कर शीघ्र प्रारम्भ करने का मार्ग प्रशस्त किया गया है।

इस महती परियोजना के लिए State Share समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। अब केन्द्र सरकार के सहयोग से इस परियोजना को और वृहद् रूप देते हुए उपलब्ध पानी की मात्रा बढ़ायी जायेगी तथा पूर्व में अनुमानित परियोजना के लिए आवश्यक राशि 37 हजार 250 करोड़ रुपये बढ़ाकर लगभग 45 हजार करोड़ रुपये की परियोजना implement की जानी प्रस्तावित है।

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान 2.0 होगा प्रारम्भ

पेयजल एवं सिंचाई हेतु निर्मित की जा रही वृहद् परियोजनाओं के साथ-साथ,

छोटे-छोटे स्तर पर 'In situ' जल संग्रहण अति आवश्यक है। इसी दृष्टि से पूर्व में जल संग्रहण एवं संरक्षण हेतु मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान की शुरुआत की गई थी। अब पुनः आगामी वर्ष से लगभग 11 हजार 200 करोड़ रुपये की राशि से मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान 2.0 शुरू किया जाएगा। इसके तहत आगामी चार वर्षों में 20 हजार गांवों में 5 लाख Water Harvesting Structures बनाये जायेंगे। प्रथम चरण में, आगामी वर्ष 5 हजार से अधिक गांवों में 3 हजार 500 करोड़ रुपये की राशि से 1 लाख 10 हजार कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं।

वन एव वन्यजीव संरक्षण के लिए वृहद स्तर पर पौधा रोपण

I. Tree Outside Forest in Rajasthan (TOFIR) कार्यक्रम के तहत 4 करोड़ पौधे वितरित किये जायेंगे।

II. Rajasthan Forestry and Bio Diversity Development Project के अन्तर्गत पौधारोपण, ओरण विकास, पौध वितरण व आजीविका संवर्द्धन गतिविधियों आदि के लिए 300 करोड़ रुपये के कार्य होंगे।

III. अरावली हिल्स को सुरक्षित रखने के लिए इसके आसपास के 30 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण होगा।

IV. गोडावन संरक्षण हेतु टनल निर्माण का कार्य प्रारंभ कराया जायेगा।

V. Black Buck हेतु जसवंतगढ़-नागौर में Habitat Development के कार्य कराये जाने प्रस्तावित हैं।

किसान सम्मान निधि बढ़ाकर 8 हजार रुपये वार्षिक

प्रदेश की GSDP में लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का है। वर्तमान में कृषि व पशुपालन से राज्य में लगभग 85 लाख परिवारों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 30 जनवरी, 2024 को सदन में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत किसानों के लिए देय वित्तीय सहायता को प्रति परिवार 6 हजार से बढ़ाकर 8 हजार रुपये वार्षिक करने की घोषणा की है। इसके लिए एक हजार 400 करोड़ रुपये वार्षिक का प्रावधान प्रस्तावित है।

गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी

प्रथम चरण के रूप में रबी, 2023-24 में गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 125 रु प्रति क्विंटल Bonus उपलब्ध करवाने का भी निर्णय लिया है। इस पर 250 करोड़ रु व्यय होंगे।

"जनता जनार्दन की आशाओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने बजट 2024-25, लेखानुदान प्रस्तुत किया है। इसमें यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मंशानुसार महिलाओं, किसानों, छात्रों, व्यापारियों एवं कार्मिकों सहित सभी वर्गों को बड़ी सौगातें दी गई हैं। आपणो अग्रणी राजस्थान के सपने को साकार करने की दिशा में इस बजट में महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं।"

-मुख्यमंत्री

एग्रीकल्चर इन्फ्रा मिशन के लिए 2 हजार करोड़ रुपये

किसानों को अधिकाधिक सम्बल के लिए Rajasthan Agriculture Infra Mission शुरू कर प्रारम्भ में 2 हजार करोड़ रु का प्रावधान किया जाएगा। इसके अन्तर्गत 20 हजार Farm Ponds, 10 हजार किलोमीटर सिंचाई पाइप लाइन, 50 हजार किसानों के लिए तारबंदी, 5 हजार कृषकों हेतु Vermi Compost इकाइयां एवं नये Agro-Processing Clusters, Food Parks तथा Horticulture Hub स्थापित करने के कार्य हाथ में लिये जायेंगे। साथ ही, 500 Custom Hiring Centres स्थापित किये जाकर Drone जैसी नई तकनीक भी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

33 लाख किसानों को "श्रीअन्न" के उच्च गुणवत्ता के बीज

Millets के उत्पादन में हमारा प्रदेश देश में अग्रणी स्थान रखता है। प्रदेश में Millets के उत्पादन को और बढ़ावा देने तथा ग्रामीण परिवारों को अपनी आवश्यकता का अनाज पैदा करने की दृष्टि से, आगामी वर्ष 12 लाख किसानों को मक्का, 8 लाख किसानों को बाजरा, 7 लाख किसानों को सरसों, 4 लाख किसानों को मूंग एवं 1-1 लाख किसानों को ज्वार व मोठ के उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है।

गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में 5 लाख पशुपालको को ऋण

प्रदेश में गोवंश संरक्षण के साथ ही, इस कार्य से जुड़े परिवारों को सहायता देने के लिए डेयरी से सम्बन्धित गतिविधियों यथा गोवंश हेतु shed, खेळी का निर्माण तथा दुग्ध, चारा, बांटा सम्बन्धी उपकरण खरीदने हेतु, एक लाख रुपये तक ब्याज मुक्त short term ऋण उपलब्ध कराने के लिए Kisan Credit Card की तर्ज पर 'Gopal Credit Card' (GCC) योजना प्रारम्भ की जाएगी। योजना में, प्रथम चरण में लगभग 5 लाख गोपालक परिवारों को ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। इस योजना पर आगामी वर्ष 150 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

आगामी वर्ष में 70 हजार सरकारी भर्तियां

युवाओं के रोजगार हेतु आगामी वर्ष सरकार के अधीन लगभग 70 हजार पदों पर भर्तियां की जाएंगी। साथ ही, युवाओं की counselling और मार्गदर्शन के माध्यम से निजी क्षेत्र में उनके स्वर्णिम करियर निर्माण के लिए प्रदेश के समस्त संभाग मुख्यालयों पर युवा साथी केन्द्र स्थापित होंगे। इस हेतु 10 करोड़ रुपये व्यय होंगे। युवाओं को employable बनाने के लिए

I. प्रत्येक संभाग में रोजगार मेलों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में campus placement के आयोजन के साथ-साथ Skill Development Training Programmes चलाये जायेंगे।

II. राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आदि का वार्षिक भर्ती परीक्षा Calendar जारी होगा।

III. मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम प्रारम्भ कर आगामी 2 वर्षों में 20 हजार युवाओं एवं लोक कलाकारों को Guide / Hospitality पारम्परिक कला सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जाएगा।

पेपर लीक की रोकथाम के लिए एसआईटी का गठन

प्रदेश में पेपर लीक जैसी घटनाओं की रोकथाम एवं दोषियों को सजा दिलाने के लिये Special Investigation Team (SIT) का गठन कर कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है।

KG से PG तक निःशुल्क शिक्षा

प्रदेश में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा को केन्द्र सरकार द्वारा लाई गयी 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020' के अनुसरण में गुणवत्तापूर्ण बनाया जाएगा। सभी वंचित वर्गों तक भी शिक्षा की पहुँच सुलभ करने के लिए आगामी वर्ष से अल्प आय वर्ग, लघु/सीमान्त/बटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के परिवार के छात्रा-छात्राओं को KG से PG तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी।

राजकीय शिक्षण संस्थाओं में निर्माण, रिपेयर के लिए 250 करोड़ रुपये

प्रदेश की राजकीय शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा एवं शिक्षण का बेहतर वातावरण उपलब्ध करवाने की दृष्टि से भवनों के repair कक्षा-कक्षों एवं बालिका toilets के निर्माण तथा विभिन्न विभागों के अन्तर्गत संचालित hostels एवं residential schools में सुविधाओं के उन्नयन तथा repair व maintenance कार्यों हेतु 250 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

अटल इनोवेशन स्टूडियो एवं एक्सीलेटर्स

प्रदेश के युवाओं की ऊर्जा एवं उनके 'Out of the Box' Ideas का समाज, प्रदेश एवं देश की उन्नति में सार्थक योगदान हो तथा इसके साथ ही उन्हें अपने सपने साकार करने के समुचित अवसर मिलें, इस दृष्टि से जयपुर, बीकानेर, भरतपुर एवं उदयपुर में 'Atal Innovation Studio and Accelerators' की स्थापना की जाएगी। accelerators में software coding, Robotics Fab Lab, एवं Multi Media/VFX सम्बन्धी विश्वस्तरीय सुविधायें उपलब्ध होंगी। इस हेतु एक हजार करोड़ रुपये व्यय होंगे।

70 लाख विद्यार्थियों को एक हजार रुपये की सहायता

आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के छात्रा-छात्राओं को भी शिक्षा हेतु आवश्यक स्कूल बैग, किताबें तथा यूनिफॉर्म उपलब्ध हो सकें, इस दृष्टि से राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा एक से आठवीं तक के समस्त विद्यार्थियों तथा कक्षा नौ से बारहवीं तक की छात्राओं को आगामी वर्ष प्रति विद्यार्थी एक हजार रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। इस प्रकार लगभग 70 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हो सकेंगे।

विश्वस्तरीय हाइटेक टाउनशिप

जयपुर के निकट 'High Tech City' विकसित की जाएगी। इस 'High Tech' Township में IT, Fintech, Financial Management, AI/ML सहित अन्य New Age Subjects के संस्थानों, कम्पनियों को स्थापित करने हेतु special incentives दिये जायेंगे। साथ ही, यहां world class city के अनुरूप निवासियों को समस्त सुविधायें भी उपलब्ध हो सकेंगी।

मिशन ओलम्पिक 2028 में 50 खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय सुविधायें

Olympics में भाग लेने के लिए प्रदेश के 50 प्रतिभाशाली युवाओं को Training /Kit/Coach सहित सभी विश्वस्तरीय सुविधायें उपलब्ध कराने की दृष्टि से 'Mission Olympics -2028' चलाया जाएगा। इसके लिए जयपुर में Centre of Excellence for Sports भी स्थापित किया जायेगा। इस हेतु 100

करोड़ रु का प्रावधान प्रस्तावित है।

बालिकाओं के लिए स्पोर्ट्स इन्स्टीट्यूट्स

जयपुर, भरतपुर एवं उदयपुर में बालिकाओं के लिए 'Residential Girls Sports Institutes' 25-25 करोड़ रुपये की राशि से स्थापित किया जाना प्रस्तावित हैं।

बालिकाओं के लिए 'लाडो प्रोत्साहन योजना'

बालिकाओं को प्रारम्भ से ही समुचित शिक्षा एवं सम्बल प्राप्त हो, जिससे वह उन्नति के पथ पर अग्रसर होकर समाज व देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकें। इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर एक लाख रुपये का Saving Bond प्रदान करने हेतु 'लाडो प्रोत्साहन योजना' प्रारम्भ की जाएगी।

प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना की राशि में 1500 रुपए की बढोतरी

वर्तमान में 'प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना' के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रथम बच्चे के लिए दो किस्तों में 5 हजार रुपये दिये जाने का प्रावधान है। आगामी वर्ष प्रदेश में प्रथम चरण के रूप में इसे बढ़ाकर 6 हजार 500 रुपये किया जाएगा। इस पर 90 करोड़ रुपये व्यय प्रस्तावित है। साथ ही, प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एक आंगनबाड़ी को स्वास्थ्य जांच, पोषण तथा Pre - school Education की दृष्टि से उत्कृष्ट बनाने के लिए आदर्श आंगनबाड़ी के रूप में उन्नयन किया जायेगा। इस हेतु 20 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में अब 'Day Care' Package का भी लाभ

केन्द्र सरकार द्वारा 'आयुष्मान भारत योजना' के माध्यम से देश के कोने-कोने में आम आदमी को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। पूर्व में प्रदेश में 'भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना' के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को चिकित्सा सुविधा सरकारी के साथ ही निजी चिकित्सालयों में भी उपलब्ध कराये जाने की पहल की गई थी। आज कैंसर जैसी गम्भीर बीमारियों का इलाज भी नई तकनीक से OPD में सम्भव हो रहा है। अतः आमजन को गम्भीर बीमारी की स्थिति में और अधिक राहत देने की दृष्टि से प्रदेश में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में IPD के साथ-साथ 'Day Care' Package जोड़ा जाएगा।

लखपति दीदी योजना में 5 लाख परिवारों की आय बढ़ेगी

माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण हेतु प्रारम्भ 'लखपति दीदी योजना' में प्रदेश में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों में से 2 लाख 80 हजार महिलायें एवं उनके परिवार, एक लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आमदनी

"बजट राज्य सरकार के सुराज संकल्प के सपने को साकार करने वाला और प्रदेश को विकास एवं उन्नति के पथ पर अग्रसर करने वाला साबित होगा। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास एवं सबका कल्याण' को केन्द्र में रखते हुए इस बजट में अंतिम छोर पर खड़े प्रत्येक व्यक्ति को भरपूर राहत देने की ठोस पहल की गई है।" -मुख्यमंत्री

कर रहे हैं। इस योजना को और अधिक गति देते हुए आगामी वर्ष 5 लाख परिवारों की आय एक लाख रुपये वार्षिक तक ले जाने का कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

मेडिकल कॉलेजों का कार्य प्राथमिकता से पूरा होगा

प्रदेश में तृतीय चरण में 4 हजार 875 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किये जाने वाले 15 मेडिकल कॉलेजों का कार्य प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा। साथ ही, सड़क दुर्घटनाओं में मानव जीवन को बचाने के लिए आगामी वर्ष प्रदेश के Highways पर 25 Advanced Life Support Ambulances उपलब्ध करवायी जाएंगी।

योग दिवस पर होंगे वृहद् आयोजन

अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस-21 जून, 2024 के अवसर पर ब्लॉक स्तर तक वृहद् रूप से आयोजन किये जायेंगे तथा प्रदेश में आयुष कार्यक्रम के संचालन के लिए आगामी वर्ष लगभग 250 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन एक हजार से बढ़ाकर 1150 रुपए

30 जनवरी, 2024 को सदन में, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जरूरतमंदों को 1 हजार 500 रुपये प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के संकल्प को पूरा करने की दिशा में प्रथम चरण में वर्तमान में देय एक हजार रुपये मासिक पेंशन को

बढ़ाकर आगामी वर्ष से एक हजार 150 किया जाएगा। इस हेतु आगामी वर्ष एक हजार 800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान प्रस्तावित है।

वरिष्ठ नागरिकों को रोडवेज बसों में अब 50 प्रतिशत छूट

प्रदेश के 60 से 80 वर्ष तक की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को रियायती यात्रा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य की सीमा में रोडवेज बसों के किराये में वर्तमान में दी जा रही 30 प्रतिशत छूट को बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाना भी प्रस्तावित है।

दिव्यांगों के लिए जिला स्तर पर पुनर्वास केन्द्र

दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए उनके कौशल विकास, शिक्षा तथा चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि की आवश्यकता को देखते हुए जयपुर में Composite Regional Centre की स्थापना की जाएगी एवं Physiotherapy, Speechtherapy आदि सुविधा प्रदान करने के लिए सभी जिला मुख्यालयों पर District Disability Rehabilitation Centres (DDRC) भी स्थापित किये जाएंगे।

पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय नगरीय निकायों की ग्रांट में बढ़ोतरी

कोई भी पात्र व्यक्ति अथवा परिवार सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रह जाये, इस उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर प्रदेशभर में 'विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविरों' का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में पंचायतीराज संस्थाओं एवं स्थानीय नगरीय निकाय जैसे Grassroot Democratic Institutions को और अधिक सशक्त करने के लिए राज्य के शुद्ध कर-आय की वर्तमान में निर्धारित SFC Grant को 6.75 प्रतिशत से बढ़ाकर आगामी वर्ष के लिए 7 प्रतिशत किया जाएगा। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2024-25 में इन Institutions को 316 करोड़ रुपये की वृद्धि के साथ, कुल अनुमानित Grant 8 हजार 864 करोड़ रुपये मिल सकेगी।

राजस्थान 'अनुग्रह' सेवा प्रदायगी अधिनियम बनेगा

वर्ष 2015-16 में केन्द्रीय बजट में 'जनधन-आधार-मोबाइल' को जोड़ते हुए Direct Benefit Transfer तथा Digital Payment की मजबूत नींव सम्पूर्ण देश में रखी गई। प्रदेश में 'भामाशाह योजना' जिसका नाम पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 'जनाधार' कर दिया गया, इस कार्यक्रम को Artificial Intelligence /Machine Learning (AI/ML) / Data Cloud जैसी नई तकनीक का प्रयोग कर और आगे ले जाया जाएगा। असहाय एवं जरूरतमंद परिवारों का SMART System (Service Management with Artificial Intelligence and Real Time System) के माध्यम से स्वतः चिन्हीकरण कर उन्हें अवगत कराते हुए स्वीकृति एवं Benefit Transfer को त्वरित/पारदर्शी Online प्रक्रिया से करने के लिए राजस्थान 'अनुग्रह' सेवा प्रदायगी अधिनियम लाया जाएगा। इस हेतु 150 करोड़ रुपये से आवश्यक IT आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाएगा।

श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना

श्रमिकों एवं street vendors को वृद्धावस्था में भी संबल प्रदान करने के लिए 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू की जाएगी। इस योजना में 60 से 100 रुपये मासिक premium देने पर, 60 वर्ष आयु पूर्ण करने के उपरान्त 2 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होगी। शेष

लगभग 400 रुपये प्रतिमाह प्रति व्यक्ति का premium राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। यह पेंशन, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन के अतिरिक्त होगी। इस योजना हेतु 350 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

डीपीसी में राजकीय कर्मचारियों को दो वर्ष की छूट

आमजन तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाने में राजकीय कर्मचारियों की महती भूमिका को देखते हुए आगामी वर्ष कर्मचारियों को पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध करवाने के लिए DPC हेतु 2 वर्ष की छूट दिया जाना प्रस्तावित है। साथ ही-

I. कार्मिकों को वेतन तथा जीपीएफ (GPF) सम्बन्धी सभी सूचनायें / विवरण Mobile App के माध्यम से Online उपलब्ध करवायी जायेंगी।

II. retirement day पर ही पेंशन परिलाभों एवं पारिवारिक पेंशन की स्वीकृतियां online जारी होंगी। पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को घर से ही Digital Life Certificate की सुविधा मिलेगी।

III. Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) के अन्तर्गत कार्मिकों एवं पेंशनर्स को CONFED (राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ) के माध्यम से दवाइयों की Door Step Delivery सुविधा प्रदान की जायेगी।

मानदेय में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी

आगामी वर्ष समस्त मानदेय कर्मियों यथा-मिनी आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, सहयोगिनी, मां-बाड़ी कार्यकर्ता, Mid-Day Meal Cook cum Helper, लांगरी, Homeguard, REXCO कर्मियों तथा नगरीय निकायों व पंचायतीराज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 10 प्रतिशत वृद्धि की जाएगी।

लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन योजना बहाल

वर्ष 2008-09 में वर्ष 1975-77 के दौरान आपातकाल के समय लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए संघर्षरत व्यक्तियों को सम्मान एवं सहायता देने की दृष्टि से मीसा, डीआईआर (DIR) आदि बंदियों हेतु प्रारम्भ की गई लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन योजना बहाल होगी। उन्हें 20 हजार रुपये पेंशन एवं 4 हजार रुपये चिकित्सा सहायता के रूप में दिये जाएंगे। यह योजना सतत रूप से संचालित रहे इसके लिए 'राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि अधिनियम' लाया जाएगा।

गौरवशाली विरासत का संरक्षण

गोविन्ददेव जी-जयपुर, मानगढ़ धाम-बांसवाड़ा, मेहंदीपुर बालाजी-दौसा, रणकपुर जैन मन्दिर-पाली, डिग्गी कल्याणजी-टोंक, बेणेश्वर धाम-डूंगरपुर, रामदेवरा-जैसलमेर, तेजाजी मंदिर (खरनाल)-नागौर, देवनारायणजी (आसींद)-भीलवाड़ा, मचकुंड-धौलपुर, जलदेवी मंदिर (रेलमगरा)-राजसमंद जैसे असीम आस्था केन्द्रों के सौन्दर्यीकरण (beautification) एवं वहां सुविधायें विकसित करने के लिए इन आस्था स्थलों के साथ-साथ गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर स्थित पूंछरी का लौठा-डीग, श्री बड़े मथुरेश जी-कोटा, त्रिनेत्र गणेश जी (रणथम्भौर)-सवाई माधोपुर आदि को सम्मिलित करते हुए प्रदेश के ऐसे 20 मन्दिरों, आस्था केन्द्रों के विकास कार्य, आगामी वर्ष में 300 करोड़ (तीन सौ करोड़) रुपये की राशि से करवाये जाएंगे।

हर जिले में एंटी रोमियो स्क्वायड, थानों में महिला हेल्प डेस्क

प्रदेश में बालिका, महिलाओं के लिए सहज एवं सुरक्षित वातावरण तैयार करने की दृष्टि से-

I. प्रत्येक जिले में Anti RomeoSquad के गठन के साथ ही शेष रहे 174 पुलिस थानों में Women Helpdesks स्थापित की जायेंगी।

II. बालिका, महिलाओं से छेड़छाड़ व अपराध की प्रभावी रोकथाम के लिए प्रत्येक जिले में प्राथमिकता के आधार पर सार्वजनिक स्थलों, बालिका छात्रावासों एवं नारी निकेतनों में CCTV कैमरे स्थापित करने के उद्देश्य से 'लाडली सुरक्षा योजना' शुरू की जाएगी।

III. बालिकाओं को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभियान के तहत Self Defence का प्रशिक्षण दिया जाता है। बालिकाओं को इस प्रशिक्षण को अधिक से अधिक संख्या में लेने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए Self Defence की उच्चतम श्रेणी-Black Belt को Sports Quota के अन्तर्गत सम्मिलित करने की घोषणा भी करती हूं।

पुलिस का होगा आधुनिकीकरण

प्रदेश में अपराधों के नियंत्रण, बेहतर कानून व्यवस्था तथा आमजन को त्वरित न्याय दिलाने के लिए-

I. पुलिस आधुनिकीकरण एवं संबंधित आधारभूत संरचना के लिए 200 करोड़ रुपये का 'Police Modernisation and Infrastructure Fund' गठित किया जाएगा।

"हमने संकल्प पत्र को राज्य सरकार के नीतिगत दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया है। संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने की दिशा में यह लेखानुदान महत्वपूर्ण है। यह लेखानुदान सरकार के लिए चुनौती भरा भी रहा। हमारी सरकार सूझ-बूझ, दूरदर्शिता और कुशल वित्तीय प्रबंधन से प्रदेश की आर्थिक प्रगति की नई इबारत लिखेगी।"

-मुख्यमंत्री

II. नवसृजित 34 पुलिस थानों में परिवादियों की त्वरित सुनवाई तथा सहयोग हेतु Cyber Helpdesk तैयार होगी। स्थानीय प्रशासन एवं विभिन्न एजेंसियों के समन्वय से hotspot क्षेत्रों में cyber crime नियंत्रण के लिए ठोस कार्ययोजना बनेगी।

महाराणा प्रताप ट्यूरिस्ट सर्किट, आर्म्ड फोर्स म्यूजियम होगा स्थापित

महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े विभिन्न स्थलों, चावण्ड-हल्दीघाटी-गोगुन्दा-कुम्भलगढ़-दिवेर-उदयपुर आदि को सम्मिलित करते हुए महाराणा प्रताप Tourist Circuit विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही, भारतीय फौज में राजस्थान के युवाओं के शौर्य व बलिदान को सम्मान देने के लिए प्रदेश में Armed Forces Museum की स्थापना के लिए DPR बनाये जाने के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

खेजड़ली-जोधपुर में अमृतादेवी बिश्नोई म्यूजियम

स्थानीय वनस्पतियों के संरक्षण तथा पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए खेजड़ली-जोधपुर में अमृतादेवी बिश्नोई Indigenous Plant Museum स्थापित किया जाएगा।

म्यूजियम का होगा उन्नयन

प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत की झांकी दिखाने वाले अल्बर्ट हॉल-जयपुर, राजकीय Museum-अलवर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर एवं जोधपुर सहित 10 प्रमुख Museums का उन्नयन करने तथा State Archives बीकानेर के अन्तर्गत Public Gallery के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये के कार्य हाथ में लिये जायेंगे।

राजस्थान इकॉनोमिक रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन

राजस्थान को अमृतकाल खण्ड के अन्त तक (वर्ष 2047 तक) देश की प्रगति में योगदान देने वाला अग्रिम राज्य बनाने के लिए आर्थिक समृद्धि के पथ पर अग्रसर किया जाएगा। इस क्रम में आमजन को राहत देने के साथ ही प्रदेश में निवेश पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। इस कड़ी में प्रदेश के आर्थिक उन्नयन के लिए 'Rajasthan Economic Revival Task Force' के गठन किया जाएगा। उद्यमिता, निवेश एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार procedural सरलता व पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है। इसको ध्यान में रखते हुए Amnesty योजनायें प्रस्तावित की गई हैं जो 31 जुलाई, 2024 तक प्रभावी रहेंगी-

I. VAT Amnesty- अन्तर्राज्यीय बिक्री के प्रकरणों, लम्बित/विवादित प्रकरणों तथा केवल ब्याज की मांग वाले प्रकरणों में बकाया राशि का 10 से 20 प्रतिशत जमा करवाने पर शेष राशि माफ की जायेगी।

II. Stamp Duty Amnesty - स्टाम्प ड्यूटी की माँग के प्रकरणों में ब्याज एवं penalty की शत-प्रतिशत छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

III. Transport Amnesty - वाहन स्वामियों को राहत प्रदान करने हेतु Amnesty योजनायें प्रस्तावित हैं, जो इस प्रकार हैं-

(i) Tax Amnesty

(a) नष्ट हो चुके वाहनों पर नष्ट होने की दिनांक के बाद के समस्त कर एवं उस कर पर देय penalty/ब्याज की छूट प्रदान की जायेगी।

(b) नष्ट हो चुके वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों पर 31 मार्च, 2023 तक के बकाया कर जमा कराने पर देय penalty/ब्याज की छूट प्रदान की जायेगी।

(ii) e-Rawanna Amnesty- खान विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर दर्ज over loading (अतिभरण) के प्रकरणों में compounding (प्रशमन) राशि में 96 प्रतिशत तक छूट प्रदान की जायेगी।

(iii) End of Life Vehicles Amnesty - पंजीकृत वाहन Scrapping सुविधा केन्द्र पर एक वर्ष तक Scrap कराये जाने वाले End of Life Vehicles का scrap किये जाने तक बकाया कर को एकमुश्त जमा कराने पर देय penalty/ब्याज में छूट प्रदान की जायेगी।

(iv) Energy Amnesty- 31 मार्च, 2023 से पूर्व कटे हुए कनेक्शन वाले कृषि विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा मूल बकाया राशि 6 Bimonthly किस्तों में जमा कराने व कृषि श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा सम्पूर्ण मूल बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर उनकी समस्त ब्याज एवं penalty राशि माफ की जायेगी।

इज ऑफ डूइंग बिजनेस होगी प्रभावी

प्रदेश में 'Ease of Doing Business' (EoDB) को प्रभावी कर आमजन को और अधिक सुविधायें उपलब्ध करवाने की दृष्टि से-

I. पक्षकारों द्वारा स्वयं भरी गई सूचनाओं के आधार पर पंजीयन हेतु उनका दस्तावेज स्वतः तैयार हो सकेगा। इसके साथ ही, आवश्यक सभी सूचनायें एवं GIS आधारित डीएलसी, स्वयं पक्षकार द्वारा अपलोड करने की सुविधा भी mobile app के माध्यम से दी जानी प्रस्तावित है।

II. दस्तावेजों के online anywhere registration के कार्य को गति देने के लिए, मौका निरीक्षण हेतु online app विकसित करते हुए qualified मौका निरीक्षकों को empanel करने की कार्यवाही की जायेगी।

III. भौतिक स्टाम्प पत्रों के स्थान पर Stamp Duty के online माध्यमों यथा e-GRAS एवं RajSTAMP को बढ़ावा दिया जायेगा तथा refund की प्रक्रिया को भी सरल व automate किया जायेगा।

IV. आमजन के साथ ही निवेशकों को अपनी परियोजना सम्बन्धी पंजीयन कार्य के लिये दर-दर नहीं भटकना पड़े, इस दृष्टि से Toll-Free Helpline के साथ ही, सभी जिलों में चरणबद्ध रूप से 24x7 कार्य करने वाले आदर्श रजिस्ट्रेशन केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।

V. प्रदेश में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित विभिन्न शुल्कों की दरों के demystification की दृष्टि से उन्हें चरणबद्ध रूप से revise कर rationalize किया जायेगा।

VI. स्वच्छ व पारदर्शी प्रशासन के सिद्धान्त की बेहतर पालना सुनिश्चित करने हेतु वाणिज्यिक कर तथा आबकारी विभागों में कार्यों की चरणबद्ध रूप से faceless management की व्यवस्था की जायेगी। इस दृष्टि से प्रदेश में Online Integrated Tax Management System, Integrated Excise Management System तथा जन-आधार Wallet को और अधिक सुदृढ़ एवं व्यापक किया जायेगा।

VII. वर्तमान में परिवहन विभाग के द्वारा e-Licence एवं e-Registration Certificate जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित करने के बाद भी आमजन को स्मार्ट कार्ड के लिये राशि 200 रुपये का अतिरिक्त व्यय करना होता है। अब आमजन को इस अतिरिक्त व्यय से मुक्त करने के लिये smart card व्यवस्था को समाप्त करते हुए e-Driving Licence एवं e-Registration Certificate की व्यवस्था लागू किया जाना प्रस्तावित है।

VIII. वाहन स्वामियों के वाहनों के Fitness Test की सुविधा को सुगम करने के लिए अपने पंजीकरण के जिले में ही fitness करवाये जाने की बाध्यता को समाप्त कर anywhere fitness की व्यवस्था लागू की जानी प्रस्तावित है।

चीनी और गुड़ पर मण्डी शुल्क समाप्त होगा

राज्य के किसानों के हितों तथा आम उपभोक्ताओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए चीनी और गुड़ पर मण्डी शुल्क को समाप्त किया जाना प्रस्तावित है।

लैण्ड टैक्स समाप्त

प्रदेश में लैण्ड टैक्स (Land Tax) समाप्त कर दिया गया है। साथ ही, पूर्व में सृजित Land Tax की demand के सम्बन्ध में Amnesty देते हुए मात्र मूल Tax की demand का 10 प्रतिशत जमा कराने पर शेष demand भी समाप्त कर दी जाएगी।

वर्ष 2024-25 के बजट अनुमानों के संक्षिप्त तथ्य

वर्ष 2024-25 में 4 लाख 86 हजार 615 करोड़ 10 लाख (चार लाख छियासी हजार छः सौ पन्द्रह करोड़ दस लाख) रुपये का कुल व्यय अनुमानित है। इन बजट अनुमानों में राजस्व व्यय 2 लाख 82 हजार 247 करोड़ 65 लाख (दो लाख बयासी हजार दो सौ सैंतालीस करोड़ पैंसठ लाख) रुपये और राजस्व प्राप्तियां 2 लाख 58 हजार 378 करोड़ 29 लाख (दो लाख अट्ठावन हजार तीन सौ अठहत्तर करोड़ उनतीस लाख) रुपये अनुमानित की गई हैं। राजस्व घाटा 23 हजार 869 करोड़ 36 लाख (तेईस हजार आठ सौ उनहत्तर करोड़ छत्तीस लाख) रुपये का अनुमानित किया गया है। राज्य का राजकोषीय घाटा 67 हजार 240 करोड़ 48 लाख (सड़सठ हजार दो सौ चालीस करोड़ अड़तालीस लाख) रुपये होना अनुमानित किया गया है। जो कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) के 3.95 प्रतिशत रहने का अनुमान है। राज्य का Dept-GSDP ratio 37.48 प्रतिशत रहना अनुमानित है। राज्य की अर्थव्यवस्था में गुणात्मक सुधार के लिए हर सम्भव कदम उठाये जायेंगे।

FRBM (Fiscal Responsibility and Budget Management) Act की धारा 5 के अन्तर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वार्षिक बजट के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले, 'मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण' (Medium Term Fiscal Policy Statement) और 'राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण' (Fiscal Policy Strategy Statement) सदन में प्रस्तुत किये गये है।

वर्ष 2024-25 के वार्षिक वित्तीय विवरण तथा अन्य बजट पत्रों के साथ कुछ अधिसूचनायें जारी की गई हैं तथा अनुदान मांगें भी प्रस्तुत की गईं। आगामी लोकसभा चुनाव के कारण बजट प्रस्तावों पर विधानसभा में चर्चा कराकर 31 मार्च, 2024 से पूर्व वार्षिक बजट पारित कराया जाना संभव नहीं होने के कारण वित्तीय वर्ष 2024-25 के पहले चार महीनों के लिए यथा-31 जुलाई, 2024 तक व्यय हेतु लेखानुदान का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस लेखानुदान में मांग संख्या 9 - निर्वाचन, मांग संख्या 36 - आपदा प्रबंधन एवं सहायता तथा मांग संख्या 41 - जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के लिए पूरे वर्ष के लिए अपेक्षित राशि की मांग की गयी है, क्योंकि इन मदों में होने वाला व्यय सामयिक है और इन्हीं महीनों में अधिक व्यय होने की संभावना है तथा इस व्यय को स्थगित नहीं किया जा सकता है। लेखानुदान की अवधि यथा 31 जुलाई, 2024 के पूर्व ही सदन के समक्ष परिवर्तित बजट अनुमान व प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिये जायेंगे।

राज्य सरकार राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाने, इसकी गौरवशाली विरासत को संरक्षित करने एवं प्रदेशवासियों को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों, किसानों, मजदूरों तथा वंचित वर्गों को सशक्त कर उनकी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए 'विकसित एवं उन्नत राजस्थान' के निर्माण की परिकल्पना को साकार किये जाने के लिए प्रभावी कदम उठाये जायेंगे।

वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी ने देश के लोकप्रिय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की अग्रलिखित पंक्तियां पढ़ते हुए लेखानुदान प्रस्तावों को स्वीकृत करने के अनुरोध के साथ सदन के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया।

"बाधायें आती हैं आयें, घिरें प्रलय की घोर घटायें,
पावों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालायें,
निज हाथों में हंसते-हंसते, आग लगाकर जलना होगा।
कदम मिलाकर चलना होगा।"

इंडिया स्टोन मार्ट-2024

2 हजार 981 करोड़ रुपये के व्यापारिक प्रस्ताव पर मुहर

▪ ईशा सैनी
सहायक जनसम्पर्क अधिकारी

प्रत्येक दो वर्ष में होने वाली पत्थर उद्योग की देश की सबसे बड़ी प्रदर्शनियों में से एक इंडिया स्टोनमार्ट का 12वां संस्करण जयपुर में 1 से 4 फरवरी तक आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इसका उद्घाटन किया। वर्तमान राज्य सरकार द्वारा किसी सेक्टर के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इतने वृहद् स्तर पर आयोजित यह पहली अन्तरराष्ट्रीय प्रदर्शनी रही।

इस प्रदर्शनी में पत्थर उद्योग से संबधित विभिन्न हितधारक जैसे उत्पादक, निर्यातक-आयातक, उपभोक्ता एवं खरीददार, विशेषज्ञ, प्रौद्योगिकी प्रदाता, वास्तुकार, बिल्डर, डेवलपर, कॉरपोरेट आदि कुल 411 एग्जीबिटर्स ने भाग लिया। जिनमें विभिन्न 9 देशों के 85 प्रतिभागी भी थें। इनमें तुर्किए (तुर्की) से 68, ईरान एवं इटली से 5-5, अमेरिका से 2, वियतनाम, स्पेन, रूस, इथोपिया एवं चीन से एक-एक प्रतिनिधि थें। इस आयोजन में 198 पत्थर उद्यमी, 195 टूल्स-मशीनरी उद्यमी, 18 संस्थागत व सेवा संबंधी एग्जीबिटर्स ने भी भाग लिया। स्टोनमार्ट में गुजरात, ओडिशा, कर्नाटक एवं झारखंड राज्यों के मंडप के साथ ही ईरानए इटली और तुर्किए के पैवेलियन आकर्षण का केंद्र रहे। जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में हुए इस आयोजन में कई देशों के पत्थर उद्योग की नामी कम्पनियां, कंपनी समूह, स्टोन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन्स के प्रतिनिधि एवं खरीददार अपने उत्पादों की मार्केटिंग करने अथवा व्यापारिक पूछताछ के लिए पंहुचे ।

उत्पादों की मार्केटिंग के लिए इटली से आए एंटोनिया डिमारिया, ईरान से आयी महनाज़ हाजी अली, उज्बेकिस्तान के फॉरेन इकॉनोमिक रिलेशन्स डिपार्टमेंट के पेकजोड़ फैज़ुल्लोव सहित सभी विदेशी प्रतिनिधि आयोजन आशान्वित दिखे।

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि इंडिया स्टोन मार्ट-2024 में कुल 948 व्यापारिक बैठकें हुई जिसमें 2 हजार 981 करोड़ रूपये के व्यापारिक प्रस्ताव पर चर्चा हुई और मुहर लगी जिसमें 150 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों एवं 189 मशीनरी एवं टूल्स एग्जीबिटर्स ने भी भाग लिया। इंडिया स्टोनमार्ट-2024 स्टोन सेक्टर से जुड़े उद्यमियों, सेवा प्रदाताओंए मैन्युफैक्चरर्स, कारोबारी जैसे एग्जीबिटर्स को दुनिया भर के उपभोक्ताओं के बीच अपने उत्पादों, सेवाओं और ब्रांडिंग को बढ़ावा देने और उनके व्यापार को बढ़ाने के लिए एक विश्व स्तरीय मंच प्रदान करता है। इस एग्जीबिशन का आयोजन राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि. सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन द्वारा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से किया गया।

मंत्रिपरिषद की प्रथम बैठक

संकल्प पत्र बना अब राज्य सरकार का नीतिगत दस्तावेज

- पूर्ववर्ती राज्य सरकार द्वारा विगत 6 महीनों में लिए गए निर्णयों की समीक्षा करेगी मंत्रीगण की समिति
- लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन होगी बहाल, -100 दिवसीय कार्य-योजना पर विस्तृत चर्चा

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में 18 जनवरी को मुख्यमंत्री कार्यालय में राज्य सरकार की पहली मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में निवर्तमान राज्य सरकार द्वारा विगत 6 माह में लिए गए प्रशासनिक निर्णयों एवं आचार संहिता लागू रहने के दौरान लिए गए फैसलों की समीक्षा करने के लिए मंत्रीगण की समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है। यह समिति इन निर्णयों की समीक्षा कर 3 महीने में अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को प्रस्तुत करेगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा के संकल्प पत्र को राज्य सरकार के नीतिगत दस्तावेज के रूप में स्वीकृति दी गई। साथ ही संकल्प पत्र के क्रियान्वयन हेतु मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेषाधिकारी की नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में राजस्थान लोकतंत्र सैनानी सम्मान निधि 2008 को बहाल करने का निर्णय लिया गया। इसके फिर से शुरू होने से देश में आपातकाल लगने पर लोकतंत्र की रक्षा हेतु जेल जाने वाले लोकतंत्र सेनानियों को फिर से पेंशन मिल सकेगी इस निर्णय के तहत लोकतंत्र सेनानियों को 20 हज़ार रुपये मासिक पेंशन तथा 4 हज़ार रुपये की मासिक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक में आरएएस भर्ती परीक्षा की तिथि, गेहूं की फसल पर एमएसपी आदि जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके साथ बैठक में राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना पर व्यापक प्रस्तुतीकरण दिया गया एवं विस्तार से चर्चा की गई। राज्य सरकार के प्रथम 30 दिवस की प्रमुख उपलब्धियों के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया।

वर्तमान सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां (18 जनवरी तक)

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

राजस्थान संकल्प पत्र 2023 में सभी गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर प्रदान करने की पालना में 1 जनवरी 2024 से 'रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना' लागू की गई। योजना में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 69.27 लाख एवं 3.56 लाख चयनित बीपीएल सहित कुल 72.83 लाख परिवार पात्र हैं। राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक परिवार को माह में अधिकतम एक गैस सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाएगी

स्वायत्त शासन विभाग एवं पंचायती राज विभाग

प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित "श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना" में दिनांक 6 जनवरी 2024 से थाली में भोजन सामग्री की मात्रा 450 से बढ़ाकर 600 ग्राम प्रति थाली (300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम चावल/मिलेट्स (श्री अन्न) खिचड़ी एवं अचार) किया गया तथा राजकीय अनुदान 17 रूपए से बढ़ाकर 22 रुपये प्रति थाली किया गया।

गृह विभाग

❖ पेपर लीक की रोकथाम एवं इसके संबंध में दर्ज मामलों में त्वरित जांच व दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने के लिए राज्य स्तर पर अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, तकनीकी सेवाएं के नेतृत्व में दिनांक 16.12.2023 को स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम का गठन किया गया।

❖ राज्य में संगठित अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किये जाने हेतु दिनांक 16.12.2023 को एक विशेष कार्यदल एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया है।

❖ केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को राज्य में अनुसंधान के लिए प्रत्येक मामले में राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इस निर्णय से सीबीआई राज्य में भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई कर सकेगी, इससे राज्य में भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।

खान विभाग

❖ राज्य में अवैध खनन/निर्गमन/भंडारण के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु खान विभाग, राजस्व, वन, पुलिस एवं परिवहन विभाग को सम्मिलित करते हुए समस्त जिलों में जिला कलक्टर्स की निगरानी में संयुक्त जांच दल गठित कर सघन अभियान चलाया जाएगा।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग तथा स्वायत्त शासन विभाग

❖ राजस्थान विकसित भारत संकल्प यात्रा में दिनांक 16.12.2023 से 17.01.2024 तक कुल 10,550 ग्राम पंचायत/शहरी स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में 2.54 करोड़ से अधिक नागरिकों सहित 1.77 लाख जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने उपस्थिति दर्ज कराई।

❖ कैम्पों में 1.58 करोड़ से अधिक व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच की गई, जिनमें से 1.78 लाख जांचें सिकल सेल के लिए की गईं।

❖ पीएम सुरक्षा बीमा योजना में 5.30 लाख से अधिक एवं पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना में 2.91 लाख से अधिक व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन किया गया।

❖ 47.60 लाख आयुष्मान भारत कार्ड की ई-केवाईसी की गई। साथ ही, 10 लाख से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये।

राज्य स्तरीय समारोह
सवाई मानसिंह स्टेडियम

राजभवन

मुख्यमंत्री निवास

75वें गणतंत्र दिवस की झलकियाँ

कर्तव्य पथ पर झलकी राजस्थान की लोक संस्कृति

दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ (पूर्व राजपथ) पर 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के लिए सजी राजस्थान की झांकी। इसमें राजस्थान की लोक संस्कृति एवं लोक जीवन को बड़ी खूबसूरती से प्रदर्शित किया गया। समारोह में झांकी ने भीलवाड़ा के फड़ चित्रांकन, कृष्ण भक्त मीरा बाई की सुंदर प्रतिमा और कालबेलिया नृत्यों के साथ मनोहारी दृश्य प्रस्तुत किया। झांकी में ऊंट पर सवार महिला-पुरुष व कठपुतलियों को नृत्य कराती महिलाएं दिखाई दे रही थीं।

बड़ी चौपड़

अमर जवान ज्योति

राष्ट्रीय अस्मिता के पुनरुत्थान की

प्राण-प्रतिष्ठा

पौष शुक्ल कूर्म द्वादशी, विक्रम संवत-2080

22 जनवरी, 2024

अयोध्या में 500 साल बाद जन्मभूमि में विराजे रामलला

मुख्य मंदिर

कुल क्षेत्रफल : 2.7 एकड़
कुल निर्मित क्षेत्र : 57,400 वर्ग फीट
मंदिर की कुल लंबाई : 360 फीट
मंदिर की कुल चौड़ाई : 235 फीट
शिखर सहित मंदिर की कुल ऊंचाई : 161 फीट
मंजिलों की कुल संख्या : 3
प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई : 20 फीट
मंदिर के भूतल में स्तंभों की संख्या : 160
मंदिर के प्रथम तल में स्तंभों की संख्या : 132
मंदिर की दूसरी मंजिल में स्तंभों की संख्या : 74
मंदिर में चबूतरे एवं मंडपों की संख्या : 5
मंदिर में द्वारों की संख्या : 12

■ **विवेक जादौन**
उप निदेशक

पांच सौ वर्ष लम्बे वनवास के बाद पौष माह शुक्ल द्वादशी, विक्रम संवत 2080 यानी 22 जनवरी, 2024 को प्रभु श्रीराम अयोध्या में अपनी जन्मभूमि में विराजमान हो गए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, 125 से अधिक परम्पराओं के साधु संत, महंत, पुजारियों सहित देश-विदेश से पधारे आमंत्रित अतिथियों की उपस्थिति में मृगशिरा नक्षत्र में श्रीराम के बालरूप नूतन विग्रह की श्रीराम जन्मभूमि पर नवीन मंदिर भूतल के गर्भगृह में प्राण-प्रतिष्ठा की गई। रामलला को जन्मभूमि में विराजित होते देख कर देश-विदेश में करोड़ों रामभक्तों का रोम-रोम राममय हो उठा। न सिर्फ हिन्दू धर्म बल्कि हजारों वर्ष प्राचीन संस्कृति वाले इस सम्पूर्ण देश के लिए यह राष्ट्र की अस्मिता और गौरव की एक तरह से पुनः प्राण-प्रतिष्ठा का अवसर था।

स्वतंत्र भारत के इतिहास का यह दुर्लभतम क्षण था। करोड़ों भारतवासी अपने-अपने घरों, मंदिरों और जिसे जहां अवसर मिला वहां एकटक दृष्टि लगा कर इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बने। यह दिव्य क्षण था, जब करोड़ों चेहरे एक साथ प्रफुल्लित हो उठे, अपने आराध्य के उस वनवास को खत्म होते देख कर, जो लगता था कि कभी खत्म ही नहीं होगा।

यह विरल क्षण था जब प्रभु के मंदिर की रक्षा और पुनः प्रतिष्ठा के लिए रखे गए धैर्य की लम्बी गाथा, जिसमें 70 साल की न्यायिक प्रक्रिया भी शामिल है, एक साथ करोड़ों लोगों के मन में तैर गई। यह वाकई अद्भुत क्षण था, जब स्वप्न को साकार होता देख रामजन्मभूमि की रक्षा के लिए 1033 ईस्वी के बाद से हुए 78 संघर्षों और अपने पूर्वजों के बलिदानों को याद करके करोड़ों आंखें बरबस ही नम हो उठीं। अयोध्या का राममंदिर सिर्फ एक और मंदिर नहीं है, यह इस देश की सनातन सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, स्वाभिमान, सहिष्णुता और सहृदयता का भाव मंदिर है।

श्रीराम जन्मभूमि देश का भाव मंदिर इसलिए है क्योंकि राम भारतवासियों के भाव हैं। वे देश, काल, समय, धर्म, सम्प्रदाय, भूगोल से परे जाने-अनजाने इस देश के मन-मन और कण-कण में समाए हैं। गोस्वामी तुलसीदासजी ने कहा है- सिय राममय सब जग जानी। करउं प्रणाम जोरि जुग पानी। पूरा संसार सीता-राम का ही स्वरूप है, अर्थात सबमें भगवान का वास है। अतः हाथ जोड़कर सबमें समाए सियाराम को प्रणाम करना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है -"रामो विग्रहवान् धर्मः। राम धर्म के मूर्त स्वरूप हैं। राम धर्म का पर्याय हैं। सीमित अर्थ में नहीं बल्कि धारयति-इति धर्मः के अर्थ में। उस धर्म के अर्थ में, जिसकी शिक्षा सभी मत-सम्प्रदाय हमें देते हैं। राजा, पुत्र, शिष्य, मित्र, पति, पिता सहित सभी भूमिकाओं में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जीवन चरित्र मानव धर्म की रक्षा और मर्यादाओं की स्थापना का जीवन्त रूप है। कबीरदास जो अपने जीवनकाल में शायद ही अयोध्या गए हों, उन्होंने कहा- एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट-घट में बैठा। एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा।। कबीरदास जी जो कपड़ा बुना करते थे, उसके रेशे में भी राम को देखते थे और उसके ग्राहक में भी राम को ही देखते थे। संसार के कण-कण में ईश्वर की अनुभूति करने का यह उदात्त विचार ही राम है।

भगवान राम भारत की अनेकता में एकता के सूत्र हैं। राम ने जब 14 वर्ष का वनवास भोगा, तो वनों में भटकते हुए दूर-दराज रहने वाले वनवासियों और दलितों को संगठित करने का कार्य किया। साधु-संतों की सेवा की और राक्षसी वृत्ति के लोगों के आतंक से उनकी रक्षा की। चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र ने साधारण तपस्वी का जीवन व्यतीत करते हुए जनमानस की तकलीफों को दूर किया और शोषितों को अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। उन्होंने उत्तर से सुदूर दक्षिण तक सभी जाति, सम्प्रदायों को साथ जोड़ने का कार्य किया। अब प्रभु राम का पांच सौ वर्ष का वनवास खत्म हुआ है तो पूरा देश राममय होकर एक साथ चलता, एक साथ बोलता और एक मन से सोचता दिखाई दे रहा है।

भारत राम में रमे हुए लोगों का देश है, स्थूल रूप में नहीं बल्कि सूक्ष्मता और गहनता में। रामजी के आदर्श, आचरण और मूल्यों को अपने दिल में स्थान देने वाला यह देश है। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी संविधान के जिस भाग तीन में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की है, उसमें श्री राम, सीता जी एवं लक्ष्मण जी का चित्र है। यह भाग हमें धर्म, लिंग, जाति, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के बिना समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की गारंटी देता है। निश्चित ही संविधान के इस भाग में श्रीराम का चित्रण सर्वथा उपयुक्त है। इस प्रकार, भारतीय जनमानस की आस्था के अनुरूप और महात्मा गांधी के आदर्शों के अनुकूल प्रजा केन्द्रित रामराज्य की संकल्पना की एक झलक हमारे संविधान में भी मिलती है।

20वीं सदी के महान संत रमण महर्षि से जब पॉल ब्रन्टन ने कहा कि मुझे लगता है कि मैं हिंदू बन जाऊं। तो महर्षि ने उन्हें उत्तर दिया कि, नहीं, तुम ईसाई जन्मे हो तो अच्छे ईसाई बनो। तुमको भी वही फल मिलेगा जो किसी हिन्दू को अच्छा हिन्दू बनने पर मिलता है। यही भारत की राम दृष्टि है, जो सभी धर्म, मत, सम्प्रदायों को साथ लेकर चलती है। ऐसा विश्वास है कि अयोध्या में रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा से राष्ट्र के गौरव और सम्मान की विश्व में प्रतिष्ठा का मार्ग निश्चित तौर पर प्रशस्त होगा।

मोक्षदायिनी अयोध्या

अयोध्या मोक्षदायिनी पुरी है। अयोध्या अविनाशी, अखंड, अविजित, मोक्षदायिनी, समृद्धिपूर्ण रही है। तभी तो अवधी भाषा में कहा जाता है- गंगा बड़ी गोदावरी, तीरथ बड़े प्रयाग। सबसे बड़ी अयोध्या जहां राम लीन्ह अवतार।

अयोध्या की पहचान विशाल है विस्तृत है और धर्मों के दायरे से कहीं बड़ी है। अयोध्या का शाब्दिक अर्थ है अ-युध्य यानी जिससे युद्ध नहीं किया जा सकता। पौराणिक इतिहास के अनुसार अयोध्या की स्थापना वैवस्वत मनु द्वारा की गई बताई जाती है। भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गौरव की आधारशिला समझे जाने वाली सप्त पुरियों में अयोध्या को पहले स्थान पर रखा गया है। अथर्ववेद में अयोध्या को स्वयं ईश्वर की बनाई नगरी के तौर पर वर्णित किया है जिसकी समृद्धि स्वर्ग के समान अक्षय और अनंत है। अयोध्या इक्ष्वाकु वंशीय शासकों के साम्राज्य

कौशल देश की राजधानी रहा है। यह केवल श्रीराम का जन्म स्थान ही नहीं है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभदेव के साथ चार अन्य तीर्थंकरों अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, अनंतनाथ का जन्मस्थान भी अयोध्या ही है। जैन परंपरा के अनुसार 24 तीर्थंकरों में से भगवान महावीर सहित 22 तीर्थंकर इक्ष्वाकु वंश के थे। भगवान बुद्ध भी स्वयं को इसी वंश का मानते थे। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार बुद्ध ने अयोध्या अथवा साकेत में 16 वर्षों तक निवास किया था। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव और नौवें गुरु श्री तेग बहादुर अयोध्या गए थे और वहां ठहरे थे। दशमेश गुरु श्री गोविन्द सिंह जी भी पटना साहेब से वापस लौटते समय अयोध्या में कुछ वक्त रुके थे। अयोध्या के नजरबाग और ब्रह्मकुंड गुरुद्वारों में इन तीनों गुरुओं की स्मृतियां हैं। श्रीराम जन्मभूमि मुक्ति संघर्ष के लिए निहंग सैनिकों का बलिदान अविस्मरणीय है। इस तरह, अयोध्या का उत्थान वास्तविक अर्थ में भारतीय सांस्कृतिक गौरव के पुनरोत्थान का आख्यान है।

भव्य और दिव्य मंदिर

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भारत सरकार द्वारा न्यायालय के निर्देश पर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम से ट्रस्ट गठित किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में पूजन कर मंदिर निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया। मंदिर का वास्तु अहमदाबाद के वरिष्ठ आर्किटेक्ट चंद्रकान्त सोमपुरा द्वारा तैयार किया गया है। मंदिर निर्माण का कार्य लार्सन टुब्रो कम्पनी द्वारा किया गया है। सलाहकार के रूप में टाटा कंसल्टेंट इंजीनियर्स ने सेवाएं दी हैं। सम्पूर्ण मन्दिर तीन मंजिला का है। प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट और मंदिर की लंबाई 360 फीट तथा चौड़ाई 235 फीट है। भूतल से 16.5 फीट ऊंचा मंदिर का फर्श बनाया गया है। भूतल से गर्भ गृह के शिखर की ऊंचाई 161 फीट है। धरती के नीचे 200 फीट गहराई तक मृदा परीक्षण तथा भविष्य के सम्भावित भूकम्प के प्रभाव का अध्ययन हुआ है। मंदिर निर्माण का कार्य देश-विदेश में लाखों रामभक्तों द्वारा ट्रस्ट को दिए गए दान से किया गया है।

यूं चला प्राण-प्रतिष्ठा कार्यक्रम

श्री रामलला के विग्रह का जिस कुटिया में निर्माण किया गया, 16 जनवरी को पूजन का प्रारंभ इसी कर्म कुटी से हुआ। इसके बाद मूर्ति का निर्माण करने वाले शिल्पी का प्रायश्चित पूजन हुआ। 17 जनवरी को श्री विग्रह का परिसर भ्रमण कराया गया तथा गर्भगृह का शुद्धीकरण सम्पन्न हुआ। इसके बाद 18 जनवरी से अधिवास प्रारंभ हुआ। दोनों समय जलाधिवास, सुगंधि और गंधाधिवास हुआ। 19 जनवरी को प्रातः फल अधिवास और शाम को धान्य अधिवास हुआ। इसी तरह 20 जनवरी को सुबह पुष्प और रत्न अधिवास, शाम को घृत अधिवास हुआ। 21 जनवरी को प्रातरू शर्करा, मिष्ठान और मधु अधिवास हुआ, शाम को औषधि और

शय्या अधिवास हुआ। भगवान राम सूर्यवंशी हैं और आदित्य भी द्वादश हैं इसलिए द्वादश अधिवास हुए। इसके अतिरिक्त 16 से 22 जनवरी 2024 तक चतुर्वेद यज्ञ हुआ। प्राण-प्रतिष्ठा के ब्रह्मा गणेश्वर शास्त्री द्राविड़, प्रमुख आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित, सुनील दीक्षित, गजानंद जोगकर, अनुपम दीक्षित, घटाटे गुरुजी ने प्राण-प्रतिष्ठा के अनुष्ठान संपन्न कराए। इसमें 15 यजमान रहे। 22 जनवरी को मध्य दिवस में श्री रामलला के विग्रह की आंखों से पट्टी खोली गई और उन्हें दर्पण दिखाया गया।

श्री रामजन्मभूमि को समर्पित डाक टिकट और एल्बम

श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की स्मृति को अक्षुण्ण बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने छह विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किए। ये डाक टिकट राम मंदिर, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, जटायु, केवटराज और मां शबरी को समर्पित हैं। इन टिकटों पर कलात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से प्रभु राम के प्रति भक्ति व्यक्त की गई है और लोकप्रिय चौपाई 'मंगल भवन अमंगल हारी' के उल्लेख के साथ राष्ट्र के विकास की कामना की गई है। इन टिकटों पर सूर्यवंशी राम के प्रतीक सूर्य की छवि है, तो इनमें पुण्य नदी सरयू का चित्र भी है। मंदिर के

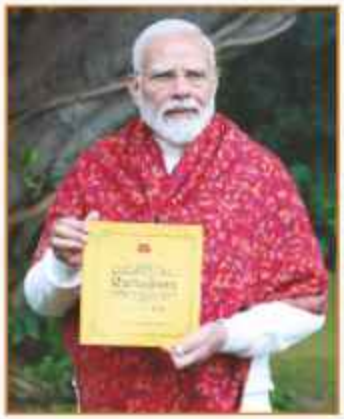

आंतरिक वास्तु के सौंदर्य को भी इन डाक टिकटों पर प्रिंट किया गया है।

विश्व के अलग-अलग देशों में प्रभु श्रीराम से जुड़े जो डाक टिकट पहले जारी हुए हैं, उनका भी एक एल्बम प्रधानमंत्री ने जारी किया। पूरे विश्व में भगवान राम, माता सीता और रामायण को बहुत गौरव से देखा जाता है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, कनाडा, चेक गणराज्य, फिजी, इंडोनेशिया, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, गुयाना, सिंगापुर आदि देशों में भगवान राम के जीवन की घटनाओं पर समय-समय पर जारी डाक टिकटों का इस एल्बम में संग्रह किया गया है। विश्व की तमाम सभ्यताओं पर राम का गहरा प्रभाव रहा है। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया सहित कितने ही देशों में आज भी रामकथा और रामलीला किसी न किसी रूप में प्रचलित हैं।

रामजन्मभूमि में राजस्थानी मिट्टी की महक

मंदिर निर्माण में नीव से लेकर भवन तक राजस्थान का अहम योगदान है। मजबूती और सुंदरता को देखते हुए मंदिर का निर्माण भरतपुर जिले के बयाना रुदावल बंशी पहाड़पुर की खदानों के लाल पत्थर से हुआ है। मुख्य भवन निर्माण में प्रवेश से निकास द्वार तक इस पत्थर का उपयोग किया गया है। नागर शैली में बन रहे इस मंदिर को कुशल कारीगरों द्वारा बंसी पाल सेंडस्टोन नाम से प्रसिद्ध इस पत्थर पर नक्काशी कर भव्य स्वरूप प्रदान किया गया है। राम मंदिर की नींव में राजस्थान के पचास से अधिक मंदिर, मठ, आश्रम और तीर्थ क्षेत्रों की मिट्टी डाली गई है।

पूरे देशभर से नींव को मजबूत बनाने में 2 हजार 587 तीर्थ क्षेत्रों की मिट्टी का उपयोग किया गया है। जयपुर से मोती डूंगरी गणेशजी, गोविंद देवजी, गलता पीठ, घाट के बालाजी, शिलामाता, झूलेलाल मंदिर अमरापुर, श्री ताड़केश्वर महादेव मंदिर, त्रिवेणी धाम, शाकंभरी माता सांभर, ज्वाला माता मंदिर जोबनेर, वीर हनुमान मंदिर सामोद, पंचखंड पीठ विराटनगर, सीकर जिले से खाटूश्याम जी, रेवासा पीठ, जीणमाता मंदिर, चूरू जिले से सालासर बालाजी, ददरेवा धाम राजगढ़, झुंझुनूं जिले से रानी सती मंदिर, सूर्य मंदिर लोहार्गल, शाकंभरी माता मंदिर उदयपुरवाटी, अलवर जिले से भर्तृहरि धाम पांडुपोल, करौली जिले से मदन मोहन जी मंदिर, कैला माता मंदिर , हल्दीघाटी, चित्तौड़गढ़, मेहंदीपुर बालाजी, त्रिनेत्र गणेश व डिग्गी कल्याण जी की मिट्टी का उपयोग नींव तैयार करने में किया गया है। मंदिर निर्माण के लिए जमीन की 50 फीट गहराई में कंकरीट की आधारशिला रखी गई। नींव में दक्षिण भारतीय ग्रेनाइट का भी उपयोग किया गया है।

मंदिर परिसर की हर दीवार में पत्थरों के बीच खाली जगह भरने के लिए राम-नाम लिखी ईंटें काम में ली गई हैं। ईंटों से रैम्प बनाया गया है। इसके अलावा ईंट का प्रयोग सीढ़ियों में भी किया गया है। राम नाम की ईंटों के अलावा 3 होल की ईंटें भी लगाई गई हैं, जो पत्थरों को परस्पर जोड़ने के लिए सलाखों के रूप में काम करेंगी। इससे पत्थरों में सैकड़ों वर्षों तक मजबूती बनी रहेगी और वे भूकंप रोधी रहेंगे।

संकल्प की सिद्धि, युगारम्भ का हर्ष

अयोध्या में राम जन्म भूमि पर नवनिर्मित मंदिर में 22 जनवरी को मंत्रोच्चारण और शंखनाद के बीच श्री रामलला की मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा के संकल्प की सिद्धि और हर्ष के दिन इस नवयुगारम्भ और अलौकिक क्षण पर सारा राष्ट्र भावविभोर था। प्रदेशभर में भी घरों, गलियों, बाजारों और जहां देखो पूरा दिन उत्सव का माहौल रहा। प्रदेशभर के कई दिवस से मंदिरों में साफ-सफाई सहित इस क्षण के लिए कई आयोजन और तैयारियां की जा रही थीं।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उनका प्राण प्रतिष्ठा दिवस पर प्रातः से ही मंदिरों में दर्शन का सिलसिला दिनभर चला। उन्होंने सालासर बालाजी और खाटू धाम जाकर शीश नवाया और वहां कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। मुख्यमंत्री रामलला की मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा दिवस की संध्या पर नगर निगम ग्रेटर जयपुर, श्री धर्म फाउंडेशन ट्रस्ट तथा जयपुर व्यापार महासंघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित श्री रामलला दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि राजस्थान के लिए यह गर्व की बात है कि यहां के बंशी पहाड़पुर के पत्थरों से अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है।

उन्होंने कहा कि शताब्दियों की प्रतीक्षा, अनेक रामभक्तों के त्याग, बलिदान तथा संघर्षों के बाद जन-जन के आराध्यदेव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव अयोध्या में सम्पन्न हुआ। हम सब भाग्यशाली हैं कि इस अलौकिक, स्वर्णिम तथा पवित्र क्षण के साक्षी बने। उन्होंने कहा कि राम हमारे रोम-रोम में बसे हैं, श्री राम हमारी आस्था ही नहीं अपितु सनातन संस्कृति के भी प्रतीक हैं। मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान श्रीराम के अनुकरणीय जीवन से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने इस अवसर पर आयोजित दीपोत्सव में दीप प्रज्वलित किया। साथ ही, आयोजित ड्रोन शो तथा आतिशबाजी कार्यक्रम में भी भाग लिया।

84 सैकंड में सिमटा 500 वर्ष का इतिहास

16वीं विधानसभा के प्रथम सत्र में माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 500 साल की सनातन की प्रतीक्षा को पूरा करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि किसी राष्ट्र के इतिहास में कभी-कभी ऐसे दुर्लभ क्षण भी आते हैं जब सदियों का इतिहास सेकंडो में सिमट जाता है। अयोध्या में 22 जनवरी को ऐसा ही क्षण आया जब 500 वर्ष का इतिहास 84 सैकंड में सिमट कर रह गया। देश ही नहीं पूरा विश्व राममय हो गया। सदियों के संघर्ष एवं राम भक्तों के बलिदान के बाद यह सपना साकार हुआ है। नव्य भव्य दिव्य मंदिर में कमलासन पर विराजे श्याम सलोने रामलला के दिव्य दर्शन से हर जन धन्य हुआ।

नए सांस्कृतिक युग की शुरुआत

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अयोध्या में प्राण-प्रतिष्ठा समारोह का सीधा प्रसारण जयपुर के प्रतापनगर स्थित प्रेम मंदिर में अन्य रामभक्तों के साथ देखा। प्रेम मंदिर पर सीधा प्रसारण देखने पहुंचे श्रद्धालुओं की आंखें श्रीरामलला की पहली अद्भुत छवि देखते हुए नम हो गई। श्री शर्मा ने इस अवसर को सकल मनोरथ का दिन बताते हुए देश में नए सांस्कृतिक युग की शुरुआत बताया।

मंगल मंदिर और देहलावास में पूजा

मुख्यमंत्री ने प्राण-प्रतिष्ठा वाले दिन सुबह मानसरोवर के मंगल मंदिर (राम दरबार) और देहलावास बालाजी मंदिर में भी विधिवत पूजा-अर्चना की कर प्रदेश में खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की।

सालासर बालाजी धाम में ध्वज स्तम्भ की पूजा

मुख्यमंत्री ने चूरू के सालासर बालाजी मंदिर में 51 फीट के ध्वज स्तम्भ की पूजा कर महाआरती में भी भाग लिया। रामलला की मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में बालाजी मंदिर के संस्थापक बाबा श्री मोहनदास जी के धूणे पर दीप जलाकर 11 हजार दीप महोत्सव का शुभारम्भ किया और प्रसाद वितरण किया।

खाटूश्याम जी मंदिर में दर्शन

मुख्यमंत्री ने सोमवार को सीकर के श्री खाटूश्याम जी मंदिर में सपत्नीक दर्शन किए। मंदिर परिसर में श्री रामलला की मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत आयोजित कीर्तन कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शामिल हुए। इस दौरान श्री शर्मा ने उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए प्रभु श्री रामलला की दिव्य प्राण-प्रतिष्ठा की शुभकामनाएं दी। उन्होंने दीपोत्सव में दीप प्रज्वलित किया और आतिशबाजी कार्यक्रम में भाग लिया।

प्राण-प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या पर महत्वपूर्ण घोषणाएं

प्रदेश में देवस्थान विभाग के 593 मंदिरों में विद्युत सज्जा, रामायण पाठ, दीप दान, महाआरती संत-महंत, पुजारियों का सम्मान किया गया। छह औद्योगिक क्षेत्रों 'श्रीराम-जानकी औद्योगिक क्षेत्र' कुन्ज बिहारीपुरा-जयपुर, सत्तासर-बीकानेर, बलारिया-सवाईमाधोपुर, जटलाव-सवाईमाधोपुर, रामसर-बाड़मेर एवं राजास-नागौर को क्रियाशील करने की भी घोषणा की। श्री शर्मा ने सीतामाता वन्य जीव अभयारण्य, प्रतापगढ़ में वनपथ, पुलिया निर्माण तथा पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए विकास कार्य एवं आयुष्मान भव: के तहत सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों एवं सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 75 हजार स्वास्थ्य मेलों का आयोजन 3 माह में करने, पीएमजेएवाई के तहत 1 करोड़ पात्र सदस्यों की ई-केवाईसी का कार्य पूरा कर कार्ड वितरण का कार्य एवं भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण भिवाड़ी द्वारा नवीन "श्रीराम-जानकी आवासीय योजना" में 208 भूखण्ड भी आवंटित किए जाने की भी उन्होंने घोषणा की।

अयोध्या के लिए विशेष बस, रेल एवं वायु सेवा

प्रदेश के सात सम्भाग मुख्यालयों जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा एवं अजमेर से अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन हेतु राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस सेवा 15 फरवरी, 2024 से प्रारम्भ की गई है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में 31 मार्च, 2024 तक 3000 तीर्थ यात्रियों को अयोध्या धाम की यात्रा करवाई जा रही है एवं 1 फरवरी से विशेष विमान सेवा का संचालन शुरू हो चुका है। साथ ही राज्य से अयोध्या के लिए रेल की आस्था ट्रेन भी प्रारम्भ की जा चुकी है।

ऊंट महोत्सव-2024

सांस्कृतिक विरासतों का संगम

रेगिस्तान के जहाज को समर्पित विश्व विख्यात "अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव-2024" का आयोजन बीकानेर में 12 से 14 जनवरी तक किया गया।

इस बार स्थानीय लोककला और शिल्प कौशल को दर्शाती थीम 'आइकंस ऑफ बीकानेर' थी। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी वर्ष 2024 को अंतरराष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया है। इसको दृष्टिगत रखते हुए पर्यटन विभाग द्वारा इस वर्ष ऊंट महोत्सव में कई भव्य और शानदार आयोजन हुए।

■ प्रवीण प्रकाश चौहान
जनसम्पर्क अधिकारी

हेरिटेज वॉक के साथ प्रारम्भ

अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव सजे-धजे ऊंट, रोबीले और पारम्परिक रंगबिरंगी वेशभूषा में सजी-धजी महिलाओं और लोक कलाकारों ने शिरकत की। हैरिटेज वॉक रामपुरिया हवेली से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए राव बीकाजी की टेकरी पर पहुंच कर खत्म हुई। इस दौरान पर्यटकों ने सांस्कृतिक धरोहर से परिचित होते हुए हवेलियों की बारीक नक्काशी का नजारा किया।

महोत्सव के दौरान रंगोली, मेहंदी एवं ड्राइंग प्रतियोगिता, पहली बार पहली घुड़दौड़, झांकियों के साथ स्थानीय कलाकारों के घूमर, कालबेलिया, पंजाब के दल द्वारा भांगड़ा, फाग, घूमर सहित अन्य नृत्यों की प्रस्तुति, बीकानेर कार्निवल, राजस्थानी लोक धुन पर ऊंटों की लंबी कूद और नृत्य, ऊंट साज सज्जा, फर कटिंग सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं, एनआरसीसी की ओर से ऊंट के दूध से बने विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी,

मिस्टर-मिस-मिसेज प्रतियोगिता, फोक नाइट "सन्स ऑफ सॉयल", समापन दिवस पर रायसर के धोरों पर हॉट एयर बैलूनिंग सहित विभिन्न गतिविधियां खास रहीं।

महोत्सव के दौरान मटका रेस, रस्साकशी से जोर आजमाइश, कुश्ती, कबड्डी, खो-खो, टिब्बा रेस, साफा बांध प्रतियोगिता सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं में देशी विदेशी सैलानियों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। पॉप और लोकसंगीत के मिश्रण से सजी सेलिब्रिटी नाइट में भारतीय पॉप और लोक संगीत का मिश्रण देखने को मिला। लोकप्रिय संगीतकार सुल्ताना 'नूरा सिस्टर्स' की शानदार प्रस्तुति से रायसर के धोरों का सर्द माहौल सूफियाना बन गया।

विकसित भारत-विकसित राजस्थान

स्वच्छ जल का संकल्प

▪ मुस्तफ़ा शेख़,
सहायक निदेशक

क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का करीब 61 प्रतिशत रेगिस्तान है। प्रदेश में उपलब्ध सतही जल देश में उपलब्ध कुल सतही जल का मात्र 1.16 प्रतिशत है। यहां सतही जल स्रोतों की कमी है, वर्षा की मात्रा एवं निरंतरता में भी कमी है और अत्यधिक भूजल दोहन से 70 फीसदी से अधिक ब्लॉक्स डार्क जोन में आ चुके हैं। राज्य के करीब 36 प्रतिशत शहर एवं कस्बे तथा 60 प्रतिशत गांवों में भूजल स्रोतों पर आधारित जल प्रदाय योजनाओं से पानी पहुंचाया जा रहा है। इन विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं कठिनाइयों के बाद भी प्रदेश के हर व्यक्ति को पीने योग्य शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार हरसंभव कदम उठा रही है।

भूगर्भीय जल का सीमित उपयोग एवं सतही स्रोतों पर आधारित योजनाएं बनाने के साथ ही वर्षा जल से भूजल पुनर्भरण एवं बारिश के पानी के समुचित संग्रहण जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। सतही जल की उपलब्धता बढ़ाने के साथ ही वर्षा जल को संग्रहित कर भू-जल स्तर में वृद्धि करना राजस्थान जैसे प्रदेश के लिए चुनौती है।

मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित विभाग के प्रमुख सचिवों की पहली बैठक में दिए गए दिशा- निर्देशों एवं संकल्प पत्र 2023 में शामिल बिंदुओं को शामिल करते हुए जलदाय विभाग ने सौ दिवसीय कार्य-योजना तैयार की है। इस कार्य योजना में जल जीवन मिशन के तहत करीब डेढ़ लाख जल कनेक्शन, 500 गांवों को हर घर जल सर्टिफिकेट, गर्मी के मौसम में पेयजल व्यवस्था के लिए 32 हजार हैण्डपंपों की मरम्मत एवं प्रगतिरत शहरी जल प्रदाय योजनाओं को समय पर पूरी करने जैसे लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

शहरी एवं ग्रामीण पेयजल व्यवस्था

राज्य के सभी 251 शहर-कस्बे विभिन्न शहरी पेयजल योजनाओं से लाभांवित हैं। इन्हें नलों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इनमें से 70 शहर-कस्बे सतही जल स्रोतों से, 125 भूजल स्रोतों से तथा 56 शहर-कस्बों को सतही एवं भूजल दोनों स्रोतों से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रदेश में 43,362 आबाद गांव एवं 78,254 आबाद ढाणियां हैं। विभिन्न पेयजल योजनाओं द्वारा 43,231 गांवों तथा 69,353 ढाणियों को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से लाभांवित किया जा रहा है। करीब 24,955 गांव एवं 52210 ढाणियां भूजल से जबकि 18,276 गांव एवं 17,143 ढाणियां सतही जल स्रोतों से लाभांवित हैं।

अमृत 2.0 के तहत स्वीकृत कार्य

केन्द्र सरकार की अमृत 2.0 योजना का लक्ष्य प्रत्येक शहर को जल सुरक्षित बनाने के लिए नल के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत 183 नगरीय निकायों में 5123 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है। इसमें 8.35 लाख नए जल कनेक्शन, 22.06 लाख पहले से मौजूद नल कनेक्शनों का संवर्द्धन किया जाना प्रस्तावित है। अमृत

2.0 के माध्यम से 33 लाख से अधिक शहरी जनसंख्या लाभांवित होगी। इस योजना का नोडल विभाग अभी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है

जल जीवन मिशन

2 अक्टूबर 2021 को जल जीवन संवाद के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था- जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का नहीं है। ये विकेन्द्रीकरण का भी एक बड़ा मूवमेन्ट है। ये विलेज ड्रिवन एवं वुमन ड्रिवन मूवमेन्ट है। इसका मुख्य आधार जन आंदोलन एवं जन भागीदारी है।

प्रधानमंत्री जी के इस विजन को ध्यान में रखते हुए राजस्थान तमाम विपरीत परिस्थितियों में जल जीवन मिशन में ऊपरी पायदान पर पहुंचने की दिशा में कदम उठा रहा है। प्रदेश के विशाल भू-भाग का दो-तिहाई हिस्सा मरूस्थल एवं प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता भी न्यूनतम है। छितराई हुई बसावट के कारण यहां छोटी-छोटी ढाणियों तक पानी पहुंचाने के लिए अत्यधिक राशि व्यय करनी पड़ती है एवं समय भी अधिक लगता है।

राजस्थान में कुल ग्रामीण परिवारों की संख्या 1 करोड़ 8 लाख से अधिक है। जल जीवन मिशन की शुरुआत के समय हमारे यहां 11.74 लाख नल कनेक्शन थे। जेजेएम में अभी तक 92.11 लाख हर घर जल कनेक्शनों की स्वीकृति हो चुकी है। इनमें से 49.34 लाख जल कनेक्शन वृहद परियोजनाओं में जबकि 42.77 लाख जल कनेक्शन अन्य परियोजनाओं (ओटीएमपी) में स्वीकृत किए गए हैं।

भूजल पुनर्भरण

पेयजल योजनाओं की निरंतरता मुख्यतः भूजल पुनर्भरण पर निर्भर करती है। राज्य सरकार के जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग (वाटरशेड) द्वारा भूजल पुनर्भरण की दिशा में कई प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें मुख्यतः एनिकट, चैकडेम, परकुलेशन टैंक, ट्रेंचेस, तालाब, जोहड़, खड़ीन, टांका, फार्म पॉण्ड जैसे कार्य किए जा रहे हैं। कुओं, ट्यूबवैल, हैण्डपंप आदि की मोबाइल एप के माध्यम से जियो-टैगिंग करने के बाद इनकी लोकेशन के आसपास वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं।

जल संसाधन विभाग- विजन एवं लक्ष्य

जल संसाधन विभाग ने मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशों एवं संकल्प पत्र में शामिल बिंदुओं को शामिल करते हुए एक कार्य योजना तैयार की है। केन्द्रीय सहायता से संचालित परियोजनाओं हेतु बेहतर समन्वय के लिए राज्य स्तर पर राजस्थान इश्यूज मॉनिटरिंग सिस्टम द रिम्स को क्रियाशील किया जाएगा। वर्ष 2047 तक के विजन को ध्यान में रखते हुए विभाग ने एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है।

प्रमुख परियोजनाएं (जल संसाधन विभाग)

नर्मदा नहर परियोजना में 1793 किलोमीटर लंबाई में वितरिकाओं एवं उप-वितरिकाओं का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 2.46 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। परियोजना में 2231 डिग्गियों का निर्माण कर 1215 डिग्गियों पर पंपिंग यूनिट स्थापित की गई हैं।

नवनेरा बैराज, कोटा 1316 करोड़ रुपये की इस परियोजना में कालीसिंध नदी पर डायवर्जन बैराज बनाया जा रहा है। इस परियोजना का लाभ कोटा, बूंदी एवं बारां जिलों को मिलेगा।

धौलपुर लिफ्ट सिंचाई एवं पेयजल परियोजना : 852 करोड़ रुपये की इस परियोजना के तहत चम्बल नदी से पानी लिफ्ट कर 256 गांवों के 39 हजार 980 हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र में स्प्रिंकलर पद्धति द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। परियोजना में पेयजल के लिए 10 प्रतिशत पानी आरक्षित है।

ईसरदा पेयजल आपूर्ति परियोजना : ईसरदा बांध बीसलपुर के डाउन स्ट्रीम में ग्राम बनैठा तहसील उनियारा, टोंक के पास बनास नदी पर बनाया जा रहा है। इससे दौसा जिले के 1079 गांव एवं 5 शहर तथा सवाई माधोपुर जिले के 177 गांव एवं एक शहर को पेयजल आपूर्ति प्रस्तावित है। परियोजना से कुल 19 लाख की आबादी को सतही पेयजल से लाभान्वित किया जाएगा।

परवन वृहद् बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना : यह परियोजना कोटा, बारां एवं झालावाड़ जिले के लोगों को पेयजल, सिंचाई एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाई गई है। 7355 करोड़ रुपये लागत की इस परियोजना के तहत इन तीनों जिलों के 1821 गांवों में पेयजल तथा 637 गांवों के 2.01 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पहले चरण में 1 लाख 31 हजार 400 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई क्षमता का सृजन किया जाएगा तथा द्वितीय चरण में 70 हजार हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई क्षमता का सृजन प्रस्तावित है।

राजस्थान को मिलेगा यमुना का पानी

वर्तमान सरकार के गठन के बाद पहले ईआरसीपी और अब 30 साल पुराना यमुना जल बंटवारे का विवाद भी सुलझ गया है। यमुना के पानी का इंतजार कर रहे शेखावाटी अंचल के चुरू, सीकर एवं झुंझनूं जिलों को अब 577 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिल सकेगा। तीन जिलों के करीब 1.05 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा भी मिलेगी।

केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा की मौजूदगी में 17 फरवरी को नई दिल्ली में केन्द्र सरकार, हरियाणा सरकार एवं राजस्थान सरकार के बीच त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। एमओयू के तहत यमुना जल परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने के संबंध में सहमति बनी।

समझौते के तहत राजस्थान को हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज (ताजेवाला हैड) से पानी मिलेगा। इसके लिए 260 किलोमीटर लंबी पाईपलाइन बिछाई जाएगी।

संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना के तहत राजस्थान में 5 बैराज एवं एक बांध बनाया जाना प्रस्तावित

1. **रामगढ़ बैराज** - बारां जिले की किशनगंज तहसील में कूल नदी पर बनेगा।
2. **महलपुर बैराज** - बारां जिले के मांगरौल में पार्वती नदी पर बनेगा।
3. **नवनेरा बैराज** - कोटा जिले की दिगोद तहसील में कालीसिंध नदी पर बनेगा। यह बैराज सर्वाधिक भराव क्षमता वाला होगा जल अपवर्तन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होने के कारण राज्य सरकार ने इसका निर्माण शुरू कर दिया है।
4. **मेज बैराज** - बूंदी जिले की इन्द्रगढ़ तहसील में मेज नदी पर बनेगा।
5. **राठौड़ बैराज** - सवाई माधोपुर जिले की चौथ का बरवाड़ा तहसील में बनास नदी पर बनेगा।
6. **डूंगरी बांध** - सवाई माधोपुर में बनास नदी पर बनेगा।

Navnera Barrage, Kota

Navnera Barrage, Kota

21 जिलों की प्यास बुझाएगी संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना

पिछले माह 28 जनवरी को नई दिल्ली में राजस्थान एवं मध्य प्रदेश सरकार एवं केन्द्र के बीच एमओयू हस्ताक्षर से बहुप्रतीक्षित पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के एकीकरण सहित संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल (पीकेसी) लिंक परियोजना के रूप में चम्बल बेसिन की नदियों को आपस में जोड़कर इनके पानी के उपयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मजबूत इच्छाशक्ति एवं केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय की पहल पर यह एमओयू संभव हुआ। केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव की मौजूदगी में दोनों राज्यों के जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिवों एवं केन्द्रीय जल संसाधन सचिव ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए।

जल संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए नदियों को आपस में जोड़ने के भारत सरकार के राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम के तहत ईआरसीपी अब संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल (पीकेसी) लिंक परियोजना के नाम से मूर्त रूप लेगी। एमओयू के बाद अब राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण एवं राजस्थान व मध्य प्रदेश राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से संशोधित पीकेसी लिंक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाएगी।

पीकेसी लिंक परियोजना का लाभ राजस्थान के 21 जिलों के साथ-साथ मध्यप्रदेश के भी 13 जिलों को मिलेगा। दोनों राज्यों के 5 लाख 80 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इसमें राजस्थान का 2.80 लाख हैक्टेयर क्षेत्र शामिल है। करीब 25 लाख किसान परिवारों को सिंचाई के लिए पानी एवं प्रदेश के 21 जिलों की लगभग 40 प्रतिशत आबादी को अगले तीन-चार दशक तक पेयजल सुविधा मिलेगी। पहले ईआरसीपी से प्रदेश के 13 जिले लाभांवित होने वाले थे लेकिन अब प्रदेश के 21 जिलों को इसका लाभ मिलेगा। परियोजना से लाभान्वित होने वाले 21 जिले-कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, डीग, गंगापुर सिटी, खैरथल-तिजारा, कोटपुतली-बहरोड़, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, ब्यावर, अजमेर एवं केकड़ी हैं।

केन्द्र सरकार ने संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना को नदियों को जोड़ने की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के हिस्से के रूप में शामिल करने के साथ ही इसे प्राथमिकता वाली लिंक परियोजनाओं में शामिल किया है। इस परियोजना से चंबल नदी बेसिन में उपलब्ध जल संसाधनों का बेहतर उपयोग करने में मदद मिलेगी। बड़े बांध एवं तालाबों में पानी संचय कर इसका उपयोग सिंचाई, पेयजल के साथ ही औद्योगिक जरूरतों के लिए किया जाएगा। संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना के तहत मध्यप्रदेश में पार्वती नदी पर कुम्भराज बांध, कुनो एवं सहायक नदियों पर एसएमआरएस बांध, कालीसिंध की सहायक नदी लखन्दर पर लखन्दर बैराज एवं कुंडलिया बांध स्थल के ऊपर रंजीत सागर बांध तथा गांधीसागर बांध पर 7 योजनाएं बनाया जाना प्रस्तावित है।

परियोजना के तहत राजस्थान में 5 बैराज एवं एक बांध बनेगा। इसमें बैराज का निर्माण जल अपवर्तन एवं बांध का निर्माण जल संग्रहण के लिए किया जाएगा। इसमें कुल नदी पर रामगढ़ बैराज, पार्वती नदी पर महलपुर बैराज, कालीसिंध नदी पर नवनेरा बैराज, मेज नदी पर मैज बैराज, बनास नदी पर राठौड़ बैराज तथा बनास पर ही डूंगरी बांध बनेगा। साथ हीए रामगढ़ बैराज से डूंगरी बांध तक जल स्थानांतरण प्रणाली भी विकसित की जाएगी। ईसरदा बांध एवं 26 मौजूदा बांधों को इससे जोड़ा जाएगा, परियोजना के रास्ते में आने वाले बांधों एवं बड़े तालाबों में पानी भरा जाएगा जिससे उस क्षेत्र का भूजल स्तर बढ़ेगा। केन्द्र सरकार संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक मैकेनिज्म तैयार करेगी। परियोजना में जल बंटवारे का निर्धारण नियंत्रण बोर्ड में राजस्थान एवं मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के बीच बनी सहमति एवं केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन परियोजनाओं के लिए बने दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा।

केन्द्र सरकार के सहयोग से इस परियोजना को और वृहद् रूप देते हुए उपलब्ध पानी की मात्रा बढ़ायी जाएगी तथा परियोजना के लिए पूर्व में अनुमानित राशि 37 हजार 250 करोड़ (सैंतीस हजार दो सौ पचास करोड़) रुपये को बढ़ाकर लगभग 45 हजार करोड़ किया जाना प्रस्तावित है।

स्वस्थ भारत की संकल्पना हो रही साकार

- प्रदेश में 11741 स्वास्थ्य शिविर आयोजित
- 1 करोड़ 84 लाख से अधिक लोग स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ लेने पहुंचे

■ तरूण जैन
सहायक निदेशक

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर संचालित विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रति प्रदेश में अपार उत्साह देखने को मिला। इस यात्रा से स्वस्थ और समृद्ध भारत की संकल्पना ने मूर्त रूप लिया। यात्रा के दौरान आयोजित स्वास्थ्य शिविरों में लाखों लोगों ने उपस्थिति दर्ज कराई और केन्द्र प्रवर्तित स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ प्राप्त किया।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निरन्तर प्रयासों से 11741 प्रदेशभर में आयोजित शिविरों में 1करोड़ 84 लाख 49 हजार से अधिक से अधिक लोग स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ लेने पहुंचे। शिविरों में अब तक करीब 25 लाख 68 हजार से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने के संकल्प में राजस्थान प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक ऐसी अभिनव पहल है जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर पात्र व्यक्ति को योजनाओं का पूरा लाभ मिले। यात्रा के तहत आयोजित स्वास्थ्य शिविरों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीबी, गैर संचारी रोग यथा हायपरटेंशन, हृदय रोग, डायबिटीज, सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग एवं रैफरल सेवाएं, हीमोग्लोबिन जांच एवं उपचार सेवाएं निःशुल्क प्रदान की गई।

टीबी मुक्त राजस्थान की ओर तेजी से बढ़ते कदम

प्रदेश में 1 करोड़ 48 लाख 57 हजार से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की गयी और 1 लाख 89 हजार से अधिक लोगों को टीबी की जांच के लिए चिकित्सा संस्थानों में रैफर किया गया। इन शिविरों में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 1 लाख 83 हजार से अधिक लोगों की सहमति ली गयी एवं 14 हजार से अधिक निक्षय मित्र के रूप में पंजीकृत हुए। साथ ही निक्षय योजना के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में लाभ के लिए 20 हजार से अधिक लोगों की एनपीवाई बैंक अकाउंट डिटेल एकत्रित की गयी।

1 करोड़ से ज्यादा लोगों को स्वस्थ जीवनशैली के लिए किया प्रेरित

शिविरों में स्क्रीनिंग कर गैर संचारी रोगों की जांच के लिए 6 लाख 18 हजार से अधिक लोगों को उच्च चिकित्सा संस्थानों के लिए रैफर किया गया। साथ ही 1 करोड़ 2 लाख से अधिक लोगों को जीवनशैली से जुड़े रोगों यथा कैंसर, हृदय रोग, डायबिटीज जैसे रोगों से बचाव के लिए स्वस्थ जीवनशैली संबंधी परामर्श दिया गया। हायपरटेंशन संबंधी रोग के लिए 94 लाख 93 हजार से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की गई। इनमें से 5 लाख 73 हजार से अधिक लोगों में इस रोग के संभावित लक्षण दिखे।

प्रदेश के 10127 संस्थान बने आयुष्मान आरोग्य मंदिर

डायबिटीज के लिए 92 लाख 10 हजार से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग में 3 लाख 61 हजार से अधिक लोग इस रोग से ग्रसित मिले। सिकल सेल एनीमिया के लिए 63 हजार से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग में 1193 लोगों में इस बीमारी के लक्षण मिलने पर उच्च चिकित्सा संस्थानों में रैफर किए गये। अब तक राज्य में 10 हजार 127 स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों (HWC) को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में परिवर्तित किया गया है। यात्रा के दौरान आयोजित शिविरों में 56 लाख 21 हजार से अधिक लाभार्थियों की हीमोग्लोबिन की जांच की गयी, जिनमें से 4 लाख 13 हजार 794 लोगों में खून की कमी यानी एनीमिया की पुष्टि की गयी। इनमें से 4 लाख 13 हजार से अधिक लोगों का उपचार भी प्रारम्भ कर दिया गया।

अंगदान के ऑनलाइन पंजीकरण में राजस्थान अव्वल

यात्रा में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने का नवाचार भी शामिल किया गया। इसका परिणाम यह रहा कि नेशनल ऑर्गन एण्ड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइजेशन के पोर्टल पर अंगदान की शपथ लेकर ऑनलाइन रजिस्ट्री करवाने में राजस्थान प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में अंगदान की शपथ लेकर नोटो की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्री करवाने का आह्वान किया गया था।

सौर ऊर्जा से रोशन होगा राजस्थान

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश विकास के नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देशों की कतार में शामिल करने का संकल्प लिया। भारत की बढ़ती ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने 22 जनवरी 2024 को रामलला की मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री सूर्योदय जैसी महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की। इस योजना में देश के एक करोड़ घरों की छत पर सोलर पैनल उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे न केवल देश में गरीबों और मध्यम वर्ग के बिजली बिल पर होने वाला खर्च कम होगा, बल्कि भारत ग्रीन एवं क्लीन एनर्जी क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा।

राजस्थान वह राज्य है जहां सोलर एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा देने की सर्वाधिक संभावनाएं मौजूद हैं। थार का वृहद रेगिस्तान, साल में 11 महीनों में निकलने वाली सूर्य की प्रखर एवं सघन किरणें, सौर ऊर्जा संयंत्र तथा बड़े सोलर पार्क स्थापित करने के लिए आवश्यक अनुपजाऊ भूमि की उपलब्धता जैसी प्राकृतिक अनुकूलताओं के साथ ही सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने वाली राज्य सरकार की नीति से राजस्थान आने वाले समय में इस क्रांति का अगुवा बनने जा रहा है।

प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के माध्यम से देश को रोशन करने के श्री मोदी के भगीरथी संकल्प को साकार करने के मद्देनजर राज्य सरकार ने सीकर, जयपुर एवं जोधपुर में एक-एक हजार नए रूफ टॉप सोलर पैनल लगाने का कार्य भी शुरू कर दिया है।

■ सविता
सहायक जनसम्पर्क अधिकारी

राजस्थान सौर ऊर्जा में असीम संभावनाओं का क्षेत्र

राजस्थान में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। राज्य सौर ऊर्जा स्थापना में देश में प्रथम स्थान पर है। राज्य में 31 दिसंबर 2023 तक 15195.12 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है। प्रदेश को इस क्षेत्र में और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश के ऊर्जा राज्यमंत्री श्री हीरालाल नागर ने दिल्ली में केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली आपूर्ति तथा किसानों को प्रतिदिन 6 घंटे आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र की कोयला आधारित विद्युत इकाइयों के अनावंटित कोटे से राज्य को 1 हजार मेगावाट बिजली के अस्थायी आवंटन का आग्रह किया। इन मुद्दों पर चर्चा करने के साथ ही श्री सिंह ने उन्हें ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में महाराष्ट्र सरकार के मॉडल को अपनाने का सुझाव दिया।

केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री के इस आग्रह के बाद प्रदेश के ऊर्जा राज्यमंत्री श्री हीरालाल नागर ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे से बीते दिनों मुलाकात की। श्री नागर ने श्री शिंदे से सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देकर किसानों को दिन में बिजली आपूर्ति करने के महाराष्ट्र मॉडल की जानकारी ली।

पहली बार ब्यावर के 3 गांवों के 183 घर हुए रोशन

प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के तहत ग्राम पंचायत आसन के सरूपा, अलजेरीया और मेडिया के 183 घरों को सौर उर्जा के माध्यम से रोशन किया गया। इसके लिए हर घर में सोलर पॉवर बैंक जिसमें 5 एलईडी, 1 डीसी पंखा और 1 डीसी पॉवर प्लग निःशुल्क दिया गया। इससे हर घर को रोशन करने में लगभग 40,000 रुपये का खर्चा आया। अब इन गांवों के बच्चे बिजली की रोशनी में पढ़ाई कर पा रहे हैं, घरों में टीवी, मोबाइल आदि बिजली के उपकरण कार्य कर रहे हैं और गृहणियों को घर के दैनिक कार्य में सुविधा हुई।

राजस्थान से ऊर्जा विभाग के अधिकारियों का दल जल्द ही महाराष्ट्र का दौरा कर वहां की सरकार द्वारा किए गए नीतिगत बदलावों तथा इनके माध्यम से आए सफल परिणामों का अध्ययन करेगा तथा राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप इन्हें यहां लागू करने के संबंध में रणनीति तैयार करेगा।

- 5 लाख से अधिक घरों में सोलर प्लांट लगाकर प्रतिमाह 300 यूनिट तक बिजली निशुल्क दी जाएगी।
- प्रदेश में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की प्रभावी क्रियान्विति के लिए प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का गठन किया जायेगा।
- राज्य में Invit/ ToT लाने के साथ सभी बिजली कम्पनियों/निगमों का विशेषज्ञों की सहायता से Business Plan तथा दस वर्ष की अवधि ध्यान में रखते हुए Resource Adequacy Plan बनाकर समयबद्ध रूप से लागू किया जायेगा।

सौर ऊर्जा की ओर बढ़ते कदम

पी.एम. कुसुम योजना नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 में देश में किसानों के लिए ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इसके माध्यम से किसान अपनी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्रों से बिजली उत्पादित कर सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं। इस दिशा में राज्य सरकार ने भी अपने नीतिगत दस्तावेज संकल्प पत्र में घोषणा की है कि इसके अंतर्गत प्रदेश में सभी मौजूदा ट्यूबवेलों का सौर ऊर्जा द्वारा शत-प्रतिशत संचालन सुनिश्चित किया जाएगा।

5300 करोड़ रुपये की सौर परियोजनाओं की आधारशिला, राष्ट्र को अर्पण

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 16 फरवरी को 'विकसित भारत-विकसित राजस्थान' कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की 17 हजार करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण, शिलान्यास कार्यक्रम में राजस्थान में लगभग 5300 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण सौर परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई और राष्ट्र को समर्पित किया गया। उन्होंने बीकानेर में 300 मेगावाट की एनएलसीआईएल बरसिंगसर सौर परियोजना की आधारशिला रखी। साथ ही एनएचपीसी लिमिटेड की 300 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी, जिसे बीकानेर राजस्थान में विकसित किया जाएगा एवं 300 मेगावाट की एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड नोखरा सोलर पीवी परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने राजस्थान में 2100 करोड़ रुपये से अधिक की विद्युत ट्रांसमिशन क्षेत्र की परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित किया। परियोजनाओं में विभिन्न सौर ऊर्जा क्षेत्रों से बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।

मजबूत सड़क नेटवर्क से विकसित हो रहा है राजस्थान

■ रामसिंह
सहायक निदेशक

सड़क नेटवर्क के मामले में राजस्थान देश में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर रहा है। बड़े एक्सप्रेस-वे, व्यावसायिक गलियारों के विकास से प्रदेश के जिले देश के बड़े औद्योगिक नगरों से सीधे जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गो से लेकर ग्रामीण सड़कों की बेहतर कनेक्टिविटी के मामले में राजस्थान देश का अग्रणी राज्य बनता जा रहा है। आज राजस्थान पक्की सड़क नेटवर्क के मामले में देश में चौथे स्थान पर है। दिल्ली बडौदरा राष्ट्रीय गलियारा एवं अमृतसर जामनगर व्यावसायिक गलियारे से राजस्थान देश का औद्योगिक हब बनेगा।

पिछले लगभग 10 सालों में भारत सरकार द्वारा प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से 53 हजार करोड़ से ज्यादा की लागत की परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान में 5 हजार करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री 8-लेन दिल्ली-मुंबई ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट (एनई-4) के तीन पैकेजों अर्थात बौंली-झालाई रोड से मुई विलेज सेक्शन, हरदेवगंज गांव से मेज नदी सेक्शन और तकली से राजस्थान, मध्य प्रदेश सीमा तक का सेक्शन का उद्घाटन किया।

ये सेक्शन क्षेत्र में तेज और बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे। ये सेक्शन वन्यजीवों के निर्बाध आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए छलावरण के साथ पशु अंडरपास और पशु ओवरपास से लैस हैं। इसके अतिरिक्त, वन्यजीवों पर ध्वनि प्रभाव को कम से कम करने के लिए ध्वनि अवरोधकों का भी प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री ने काया गांव में एनएच-48 के दक्षिणपुर-शामलाजी सेक्शन के साथ देबारी में एनएच-48 के चित्तौड़गढ़-उदयपुर राजमार्ग खंड को जोड़ने वाले 6-लेन ग्रीनफील्ड उदयपुर बाईपास का भी उद्घाटन किया। यह बाईपास उदयपुर शहर की भीड़भाड़ कम करने में सहायक होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कई अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया जिससे राजस्थान के झुंझुनूं, आबू रोड और टोंक जिलों में सड़क आधारभूत अवसंरचना में सुधार होगा।

व्यावसायिक गलियारा

भारतमाला परियोजना के तहत राज्य से गुजरने वाली दो महत्वपूर्ण परियोजनाएं दिल्ली बडौदरा एक्सप्रेस वे एवं अमृतसर जामनगर व्यावसायिक गलियारा हैं। दिल्ली बडौदरा राष्ट्रीय गलियारा 8 लेन का ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे है जिसमें से लगभग 374 किलोमीटर का हिस्सा प्रदेश के अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा से गुजर रहा है। इसके एक हिस्से को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्र को समर्पित कर चुके है। इसी राष्ट्रीय गलियारे के एक हिस्से के रूप में जयपुर से बांदीकुई तक 67 किलोमीटर के लिंक एक्सप्रेस-वे का काम प्रगति पर है।

इसी प्रकार अमृतसर जामनगर व्यावसायिक गलियारे का लगभग 637 किलोमीटर हिस्सा प्रदेश के हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर जिले से गुजर रहा है। इसका कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है।

दिल्ली बडौदरा राष्ट्रीय गलियारे एवं अमृतसर जामनगर

विकसित भारत-विकसित राजस्थान

व्यावसायिक गलियारे के पूर्ण होने से प्रदेश के पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्र सहित सम्पूर्ण प्रदेश को देश के बड़े व्यावसायिक शहरों तक सीधी एवं त्वरित कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे प्रदेश के पर्यटन एवं आर्थिक एवं औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। राष्ट्रीय राजधानी से सीधे जुड़ाव से प्रदेश के कई महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को विकेन्ड डेस्टीनेशन के तौर पर बढावा मिलेगा। इससे रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे तथा प्रदेश के विभिन्न जिलों के फल एवं सब्जी उत्पादक किसानों को बड़े बाजारों तक सीधी पहुंच मिलने से उनकी आय में वृद्धि होगी।

जनजातीय समूहों को मुख्य धारा से जोड़ने की पहल

देश भर में विशेष रूप से कमजोर 75 जनजातीय समूहों (पीवीजीटीज) के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर केन्द्र सरकार द्वारा शुरू किए गए महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम का लाभ प्रदेश के सहरिया बहुल बारां जिले को मिला है। इस कार्यक्रम के तहत जिले में सहरिया जनजाति बहुल 39 बसावटों को ऑलवेदर पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा।

प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की विशेष पहल है। इसके तहत बारां जिले की सहरिया बहुल पंचायत समितियों किशनगंज एवं शाहबाद में लगभग 70 करोड़ रुपये की लागत से 100 किलोमीटर लम्बाई की 39 सड़कों का निर्माण किया जाएगा।

- सड़कों के उन्नयन एवं निर्माण हेतु राज्य सड़क निधि में 1500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया।
- प्रदूषण रहित आवागमन की सुविधा हेतु बड़े शहरों के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जायेगी।
- सीतापुरा-विद्याधर नगर जयपुर मेट्रो के लिए डीपीआर बनेगी।
- प्रदेश के 60 से 80 तक की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को रोड़वेज बसों में 50 प्रतिशत छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

समाज के सबसे कमजोर समूहों के सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के लिए 11 महत्वपूर्ण घटकों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। इसके तहत सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, बिजली, सड़क, संचार और स्थायी आजीविका जैसे महत्वपूर्ण घटकों को शामिल किया गया है, ताकि इन वर्गों को समाज की मुख्यधारा में लाया जा सके।

इन कार्यों की मिली स्वीकृति

ब्लॉक	लम्बाई कि.मी.	लागत लाखों में
किशनगंज (5 सड़कें)	5.24	408.38
शाहबाद में (11 सड़कें)	18.007	1415.15

"रामसेतु" निर्माण से मिलेगी विकास को गति

बालोतरा में आरओबी का लोकार्पण

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 21 जनवरी, 2024 को बालोतरा में रेलवे ओवरब्रिज "रामसेतु" का लोकार्पण किया। यह ओवरब्रिज राष्ट्रीय राजमार्ग -112 जोधपुर - बाड़मेर रेलवे सेक्शन पर 102 करोड़ रुपये की लागत से 2 कि.मी लंबाई में 2 लेन का बना है। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि इस सेतु के निर्माण से राज्य के विकास को गति मिलेगी तथा आमजन को रेलवे क्रॉसिंग पर यातायात जाम व शहर के बीच से गुजरने वाले भारी वाहनों से संभावित दुर्घटनाओं से भी निजात मिल सकेगी। सेतु निर्माण से जसोल धाम, नाकोड़ा धाम एवं ब्रह्माधाम यात्रा जैसे धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं का आवागमन सुगम हो सकेगा। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी, उप मुख्यमंत्री एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री श्रीमती दिया कुमारी एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री के के विश्नोई सहित अन्य जनप्रतिनधि और बड़ी संख्या में गणमान्य जन उपस्थित हुए।

केंद्र सरकार जनजातीय क्षेत्रों में भी सड़क तंत्र के विकास और सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। उदयपुर में 900 करोड़ रुपये की लागत से 23 किलोमीटर के 6 लेन बाईपास ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण पूरा होने से उदयपुर शहर को अहमदाबाद जाने वाले ट्रैफिक के दबाव से निजात मिली। इसके साथ ही उदयपुर-चितौडगढ़ हाईवे का काम पूरा होने से भी आवागमन में राहत मिली है। नाथद्वारा-चारभुजा वाया हल्दीघाटी, कुम्भलगढ़ 2 लेन सड़क, देवल-डूंगरपुर-सागवाड़ा सड़क का कार्य भी 2024 में पूरा हो जाएगा तथा करीब 800 करोड़ रुपये की लागत से ब्यावर-गोमती 4 लेन हाईवे का कार्य जून-2024 तक पूरा हो जाएगा।

❖ **संकल्प पत्र की क्रियान्विती में प्रदेश में नये एक्सप्रेस वे की पहचान के लिए टास्क फोर्स गठित की जा चुकी है जो 6 माह में सम्भावित एक्सप्रेसवेज का चिन्हीकरण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।**

❖ **सरकारी निविदाओं में पारदर्शिता, कुशलता एवं प्रतियोगिता बढाने के लिए प्रभावी कदम उठाये गये है।**

राजमार्गों के विकास से राजस्थान में औद्योगिक विकास को मिलेगी गति

- जयपुर रिंग रोड फेज-2 के लिए 5 हजार करोड़ रु की मंजूरी

- जोधपुर एलिवेटेड रोड को मिली हरी झंडी

- प्रदेश को बनाया जाएगा रेलवे फाटक मुक्त

केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने राजस्थान दौरे के दौरान जयपुर रिंगरोड के द्वितीय चरण के लिए 5 हजार करोड़ व साथ ही जोधपुर एलिवेटेड रोड परियोजना को मंजूरी देने की घोषणा भी की। श्री गडकरी ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में 2500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत की 17 सड़क परियोजनाओं के लोकार्पण/शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास से यहां के सीमेंट, मार्बल और अन्य उद्योगों का तेजी से विकास होगा और राज्य प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुएगा। वर्तमान समय में हमें प्रदूषण फैलाने वाले परंपरागत ईंधन को छोड़कर बॉयो-डीजल जैसे वैकल्पिक ईंधन को अपनाने की आवश्यकता है। इसी क्रम में शीघ्र ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस-वे हाईवे पर इलेक्ट्रिक बसें चलाई

जाएंगी। इन बसों में यात्रा सुविधाजनक होगी और किराया डीजल बसों की तुलना में 30 फीसदी कम होगा। इस दौरान श्री गडकरी द्वारा दिए गए सुझाव के अनुरूप रेलवे फाटकों पर आरओबी अथवा आरयूबी का निर्माण कर प्रदेश को रेलवे फाटक मुक्त बनाने का रोडमैप तैयार करने की दिशा में बैठक में विचार-विमर्श हुआ।

1613 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण

- 1100 करोड़ रुपये की लागत से 93 किमी चित्तौड़गढ़-उदयपुर खंड के 6-लेन का निर्माण कार्य।
- 206 करोड़ रुपये की लागत से 44 किमी ब्यावर-आसींद खण्ड का 2-लेन पेव्ड शोल्डर का निर्माण कार्य।
- 186 करोड़ की लागत से 43 किमी आसींद-मांडल खण्ड का 2-लेन पेव्ड शोल्डर का निर्माण।
- 107 करोड़ की लागत से 14 किमी ब्यावर-गोमती खंड (बाघाना से मादा की बस्सी) 4-लेन का निर्माण।
- 14 करोड़ की लागत से 16 किमी भमरासिया से मोड़ी-कुराबड़ सड़क एमडीआर-150 के चौड़ाईकरण कार्य।

977 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास

- 235 करोड रुपये की लागत से 56 किमी लम्बाई के गागरिया-मुनाबाव खंड का 2-लेन पेव्ड शोल्डर निर्माण।
- 363 करोड़ रुपये की लागत से 6 किमी लम्बे सांचौर शहर में एलिवेटेड राजमार्ग निर्माण।
- 20 करोड़ रुपये की लागत से 18 किमी साकरोदा-मेनार सड़क का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य।
- 13 करोड़ रुपये की लागत से 11 किमी लम्बे बालूखल से अमलावाडा-अली-मौखमपुरा सड़क चौड़ाईकरण कार्य।
- 17 करोड़ रुपये की लागत से 13 किमी लंबी घणोली-देलवाड़ा सड़क का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य।

7 पुलों के निर्माण कार्य का शिलान्यास

- 329 करोड़ रुपये की लागत से चेनपुरा फाटक, झिलाई फाटक (टोंक), रीको फाटक (भरतपुर), हिण्डौन फाटक, हरसोली फाटक, डबल फाटक (अलवर), सांचौर फाटक (सांचौर) पर सेतुबंधन परियोजना के अंतर्गत रेलवे क्रॉसिंग पर 7 पुलों के निर्माण कार्य।

17 हजार करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 16 फरवरी 2024 को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'विकसित भारत-विकसित राजस्थान' कार्यक्रम में राजस्थान के सभी विधानसभा क्षेत्रों के लाभार्थियों को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने सड़क, रेलवे, सौर ऊर्जा, विद्युत ट्रांसमिशन, पेयजल तथा पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित 17 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने प्रदेश में रेल अवसंरचना को मजबूत करते हुए लगभग 2300 करोड़ रुपये की राजस्थान की आठ महत्वपूर्ण रेलवे परियोजना राष्ट्र को समर्पित की और उनकी आधारशिला रखी। जिन रेल परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया उनमें जोधपुर-राय का बाग-मेड़ता रोड-बीकानेर सेक्शन (277 किलोमीटर), जोधपुर-फलोदी सेक्शन (136 किमी) और बीकानेर-रतनगढ़-सादुलपुर-रेवाड़ी सेक्शन (375 किमी) सहित रेल मार्गों के विद्युतीकरण के लिए विभिन्न परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने खातीपुरा रेलवे स्टेशन को भी राष्ट्र को समर्पित किया। इस रेलवे स्टेशन को जयपुर के लिए एक सैटेलाइट स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है और यह टर्मिनल सुविधा से लैस है जहां ट्रेनें शुरू और समाप्त हो सकती हैं। प्रधानमंत्री ने जिन रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखी, उनमें भगत की कोठी (जोधपुर) में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की रखरखाव सुविधा, खातीपुरा (जयपुर) में वंदे भारत, एलएचबी आदि सभी प्रकार के रेकों का रखरखाव, हनुमानगढ़ में ट्रेनों के रखरखाव के लिए कोच केयर कॉम्प्लेक्स का निर्माण और बांदीकुई से आगरा फोर्ट रेल लाइन का दोहरीकरण आदि शामिल हैं। रेलवे क्षेत्र की परियोजनाओं का उद्देश्य रेल अवसंरचना का आधुनिकीकरण, सुरक्षा उपायों को बढ़ाना, कनेक्टिविटी में सुधार करना तथा माल और लोगों की आवाजाही को अधिक कुशलता के साथ सुविधाजनक बनाना है।

नागौर

राजसमन्द

जोधपुर

अलवर

प्रदेश में विकसित भारत के संकल्प को साकार करते पीएम श्री विद्यालय

■ मनमोहन हर्ष
संयुक्त निदेशक

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसी सिलसिले में राजस्थान में विकसित भारत के संकल्प को साकार कर शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने के लिए केन्द्र प्रवर्तित योजना पीएम श्री (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) योजना के कार्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अनवरत विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में 07 सितम्बर 2022 को राजस्थान के लिए पीएम श्री योजना के प्रथम चरण में 402 विद्यालयों का अनुमोदन किया गया था। इनमें प्रारंभिक शिक्षा के 56 व माध्यमिक शिक्षा के 346 विद्यालय शामिल हैं। केन्द्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को पीएम श्री विद्यालयों को विकसित करने के लिए कहा गया है, वर्तमान राज्य सरकार के संकल्प पत्र में भी इन विद्यालयों के विकास को प्राथमिकता दी गई है। इसी सिलसिले में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा धरातल पर ठोस और प्रभावी कदम उठाते हुए प्रदेश में पीएम श्री विद्यालयों के कार्यों को लगातार गति दी जा रही है।

पीएम श्री योजना का व्यापक लक्ष्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप स्कूली शिक्षा में सभी स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण एवं समान समावेशी शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करते हुए इन विद्यालयों को आदर्श स्कूलों के तौर पर समग्र परिवर्तन के बाद स्थापित करना है। शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने पिछले दिनों विभागीय समीक्षा बैठक में प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को पूरी तरह लागू करने के साथ ही पीएम श्री विद्यालयों के विकास पर भी फोकस करने पर बल दिया है। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव श्री नवीन जैन द्वारा भी इस योजना की सफल क्रियान्विति के लिए सतत मॉनिटरिंग की जा रही है।

पीएम श्री योजना के प्रमुख उद्देश्यों में स्कूलों में आनन्ददायी वातावरण में खेल आधारित, खोज उन्मुख एवं विद्यार्थी केन्द्रित समग्र एवं एकीकृत शिक्षण विधियों के माध्यम से विद्यार्थियों में 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप प्रमुख कौशलों का विकास करना है। प्रदेश के पीएमश्री विद्यालयों में पर्यावरण अनुकूल गतिविधियां सौर पैनल, एलईडी लाइटिंग, प्राकृतिक खेती के साथ पोषण उद्यान, अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक मुक्त वातावरण तथा जल संरक्षण व संचयन को शामिल करते हुए हरित विद्यालय के कंसेप्ट पर कार्य हो रहा है। इन विद्यालयों में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करते हुए सामाजिक, बौद्धिक एवं स्वयंसेवी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाने पर बल दिया जा रहा है, जिससे ये विद्यालय सामाजिक चेतना केंद्रों के रूप में विकसित हो सके।

केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान में जिन 402 पीएम श्री विद्यालयों की मंजूरी दी गई है, उनमें वर्तमान में करीब 2 लाख 8 हजार विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। प्रदेश में वर्ष 2023-24 में वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में इन विद्यालयों में चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर, अधिगम संवर्धन कार्यक्रम, 21वीं सदी के कौशल, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, डिजिटल लाईब्रेरी, बालिकाओं के लिए किशोरावस्था कार्यक्रम, व्यावसायिक शिक्षा अन्तर्गत

विकसित भारत-विकसित राजस्थान

इंटर्नशिप, गाइडेंस एवं कॅरियर काउंसलिंग, हरित विद्यालय गतिविधियां, सामुदायिक गतिशीलता, संस्था प्रधानों व शिक्षकों के क्षमता संवर्धन, योग शिक्षक, खेल मैदान व खेल सामग्री, आधारभूत संरचनात्मक मजबूती इत्यादि गतिविधियों का अनुमोदन किया गया है। इन सभी गतिविधियों के लिए वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2023-24 में 16394.95 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके तहत 24 करोड़ रुपये की प्रथम किस्त एसएनए में प्राप्त हो चुकी है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से सत्र 2023-24 के संबंध में अनुमोदित गतिविधियों के लिए जारी दिशा निर्देशों के बाद प्रदेश के पीएम श्री स्कूलों में योजना की गाइडलाइन के अनुसार गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है।

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की बातों पर फोकस करते हुए राज्य के पीएमश्री विद्यालयों में टीचर्स के माध्यम से विशेष मेंटोरशिप प्रदान करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 'टीचर मेंटोरशिप प्रोग्राम फोर गर्ल्स' की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। इसके तहत इन स्कूलों में मेंटोर टीचर्स तैयार किए जाएंगे, जो बालिकाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर सेंसेटिव एप्रोच के साथ कार्य करेंगे। इनको स्कूलों में बालिकाओं से किशोरावस्था, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से जुड़ी बातों पर बालिकाओं से नियमित संवाद कर उनकी पढ़ाई और जीवन स्तर में सुधार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश के पीएम श्री विद्यालयों में तीन दिवसीय स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन भी किया जा रहा है। इन शिविरों में डॉक्टर्स के अलावा मनोवैज्ञानिक फार्मासिस्ट एवं नर्स एवं अन्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सेवाएं, विद्यार्थियों के स्वास्थ्य संबंधी इंडीकेटर्स की पहचान करके स्वास्थ्य कार्ड में जानकारी अपडेट करने, चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा हेल्थ स्क्रीनिंग के आधार पर विद्यार्थियों को उचित उपचार के लिए दवाएं और परामर्श देने, अभिभावकों, शिक्षकों एवं स्थानीय नागरिकों की सहभागगिता से स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता गतिविधियों के आयोजन जैसी गतिविधियां सम्मिलित है। साथ ही स्वास्थ्य जागरूकता रैली, स्वास्थ्य संबंधी वाद-विवाद और निबंध प्रतियोगिताएं जैसी गतिविधियां भी आयोजित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से सभी पीएमश्री विद्यालयों को स्वास्थ्य कैंपों के लिए फर्स्ट एंड बॉक्स, वजन मापने की मशीन, थर्मामीटर, बीपी जांच उपकरण जैसी आवश्यक चिकित्सकीय सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है।

- अल्प आय वर्ग, लघु /सीमान्त/ बटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिक परिवारों के विद्यार्थियों को KG से PG तक नि:शुल्क शिक्षा।
- आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को 1 हजार रुपये की सहायता प्रदान की जायेगी।
- राजकीय शिक्षण संस्थानों में निर्माण, रिपेयर के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- एक हजार करोड़ रुपये की लागत से Atal Innovation Studio and Accelerators की स्थापना की जायेगी।

सूर्य सप्तमी पर विशेष आयोजन

सूर्य नमस्कार के सामूहिक अभ्यास का विश्व कीर्तिमान

- **प्रदेशभर में 88 हजार से अधिक सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों के 1.14 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों ने किया सूर्य नमस्कार**
- **विद्यार्थियों सहित 1.33 करोड़ से ज्यादा ने निभाई भागीदारी, प्रात: 10:30 बजे से 11 बजे की अवधि में एक ही समय में किया सूर्य नमस्कार**

फोटो - अनिल कुमार शाक्य
जनसम्पर्क अधिकारी

सशक्त महिला, सशक्त प्रदेश

❖ महिला सशक्तीकरण, महिला सुरक्षा और उनके सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित राज्य सरकार ने किए कई बड़े निर्णय ❖ प्रदेश के हर जिले में एक महिला थाना ❖ हर पुलिस थाने में महिला डेस्क ❖ सभी प्रमुख शहरों में एंटी रोमिओ स्क्वॉयड

■ डॉ. प्रियंका चतुर्वेदी
सहायक जनसम्पर्क अधिकारी

कोई भी देश अपनी आधी आबादी की उपेक्षा कर आगे नहीं बढ़ सकता। यदि महिलाओं की भागीदारी बराबरी की हो तो किसी भी देश के विकास की गति दोगुनी हो सकती है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है और इसके लिए प्रत्येक महिला का सुरक्षित और सफल होना आवश्यक है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से 16 दिसंबर से राजस्थान में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की। इस अवसर पर मोदी जी ने कहा, कि "विकसित भारत संकल्प यात्रा में हम गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के भविष्य पर फोकस कर रहे हैं और यही हमारे लिए देश की सबसे बड़े चार वर्ग हैं।" उनका कहना है कि ये चारों वर्ग अगर सशक्त हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे तो हिन्दुस्तान का सशक्त होना सुनिश्चित हो जाएगा।

नवनिर्वाचित राज्य सरकार महिला सशक्तीकरण, महिला सुरक्षा और उनके सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अपनी दस प्राथमिकताओं में महिला सुरक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इसके तहत प्रदेश के हर जिले में एक महिला थाना स्थापित होगा। हर पुलिस थाने में महिला डेस्क की स्थापना होगी। साथ ही सभी प्रमुख शहरों में एंटी रोमिओ स्क्वॉयड का भी गठन होगा।

क्या होता है महिला थाना ?

महिला पुलिस स्टेशन (इकाइयां या कार्यालय भी) महिला पीड़ितों के साथ होने वाले अपराधों में विशेषज्ञता वाले पुलिस स्टेशन हैं। पहली बार 27 अक्टूबर 1973 को भारत के केरल के कोझिकोड से शुरू इन स्टेशनों पर अधिकारियों को केवल कुछ अपराधों, जैसे मनोवैज्ञानिक हिंसा, घरेलू हिंसा, पारिवारिक हिंसा, साथ ही विशिष्ट धमकियों और यौन हिंसा पर प्रतिक्रिया की अनुमति है। कुछ इकाइयां समस्याग्रस्त महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता, परामर्श और चिकित्सा देखभाल प्रदान करती हैं।

क्या होती है महिला डेस्क?

पुलिस थाने में वह स्थान जहां महिलाएं बिना किसी संकोच के डेस्क की प्रभारी महिला अधिकारी को अपनी परेशानी बता सकती हैं। हेल्प डेस्क की मदद से पुलिस थाने में आने वाली महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें भी दूर होती हैं।

क्या होते हैं एंटी रोमिओ स्क्वॉयड ?

एंटी रोमियो सेल में पुलिस का दल होता है, जो कि महिलाओं, छात्राओं को छेड़ने और कमेंट करने वालों को पकड़ने का काम करता है। एंटी रोमिओ स्क्वॉयड का मुख्य लक्ष्य होता है कि महिलाएं, छात्राएं भयमुक्त होकर अपने काम करें और भयमुक्त होकर आवागमन कर सकें।

रैनबसेरों में रह रहीं महिलाओं की सुरक्षा के निर्देश

नववर्ष पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने रैनबसेरों में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके लिए कपड़ों के स्थान पर प्लाई की दीवारें व लकड़ी के दरवाजे लगाने के निर्देश दिए।

महिला अपराधों पर लगाम लगाएगी पुलिस

पुलिस महानिदेशक श्री यू. आर. साहू ने वर्ष 2024 के लिए जारी की

गई पुलिस प्राथमिकताओं में महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों और कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए योजनाबद्ध तरीके से प्रभावी कार्रवाई करने पर जोर दिया है।

विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी

केंद्र सरकार की 'मिशन शक्ति' की उप-योजना "संबल" महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, वहीं 'सामर्थ्य' उप-योजना महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए है। 'संबल' के घटकों में नारी अदालतों के एक नए घटक के साथ वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) की पूर्ववर्ती योजनाएं शामिल हैं- इसके अलावा यह योजना समाज और परिवार के भीतर वैकल्पिक विवाद के समाधान एवं लैंगिक न्याय को बढ़ावा देती है। 'सामर्थ्य' उप-योजना के घटकों में प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, शक्ति सदन, सखी निवास और पालना जैसी संस्थानों को शामिल किया गया है।

वन स्टॉप सेंटर योजना (सखी)

वन स्टॉप सेंटर एक ऐसी व्यवस्था है जहां हिंसा से पीड़ित कोई भी महिला किसी भी समय मदद ले सकती है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच की सुविधा प्रदान करना है। इसमें लगभग 8 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं।

महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल)

181 महिला हेल्पलाइन महिलाओं को आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) से जोड़कर सभी आपातकालीन सेवाओं जैसे पुलिस, एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाओं एवं सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। इसे ईआरएसएस के साथ-साथ अन्य प्लेटफार्म जैसे 1098 चाइल्ड लाइन और (NALSA) से भी जोड़ा गया है। महिला व बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में कार्यरत 34 महिला हेल्पलाइन पर अभी तक लगभग 1,36,01,533 रजिस्टर्ड कॉल से लगभग 69,75,865 महिलाओं को सहायता दी गई है।

बजट 2024-25
(लेखानुदान)
महिला सशक्तीकरण

- बालिकाओं को समुचित शिक्षा एवं सम्बल प्रदान करने के लिए बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपये का सेविंग बॉण्ड प्रदान करने हेतु 'लाडो प्रोत्साहन योजना' प्रारम्भ की जायेगी।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना की राशि में 1500 रुपये की बढ़ोतरी।
- छेड़छाड़ व अपराध रोकने के उद्देश्य से बालिका छात्रावासों एवं नारी निकेतनों में सीसीटीवी कैमरा स्थापित करने के उद्देश्य से 'लाडली सुरक्षा योजना' शुरू की जायेगी।
- लखपति दीदी योजना के तहत प्रदेश में कार्यरत स्वयं सहायता समूह का दायरा 5 लाख परिवारों तक बढ़ाया जायेगा।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत, हरियाणा में की थी। इस योजना में पीसी और पीएनडीटी अधिनियम को लागू करना, राष्ट्रव्यापी जागरूकता और प्रचार अभियान तथा चुने गए 100 जिलों में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित कार्य करना शामिल है।

महिला व बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) में अब तक 3,57,86,986 महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। इसी के साथ 432 शक्ति सदन स्थापित किये गए हैं। व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं के कारण अपने परिवार से दूर रहने वाले कामकाजी महिलाओं, जॉब ट्रेनिंग की महिलाएं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही बालिकाओं के लिए सुरक्षित और किफायती आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए शक्ति निवास की भी स्थापना की गई है। पूरे देश में अभी लगभग 500 शक्ति निवास संस्थाएं संचालित हैं।

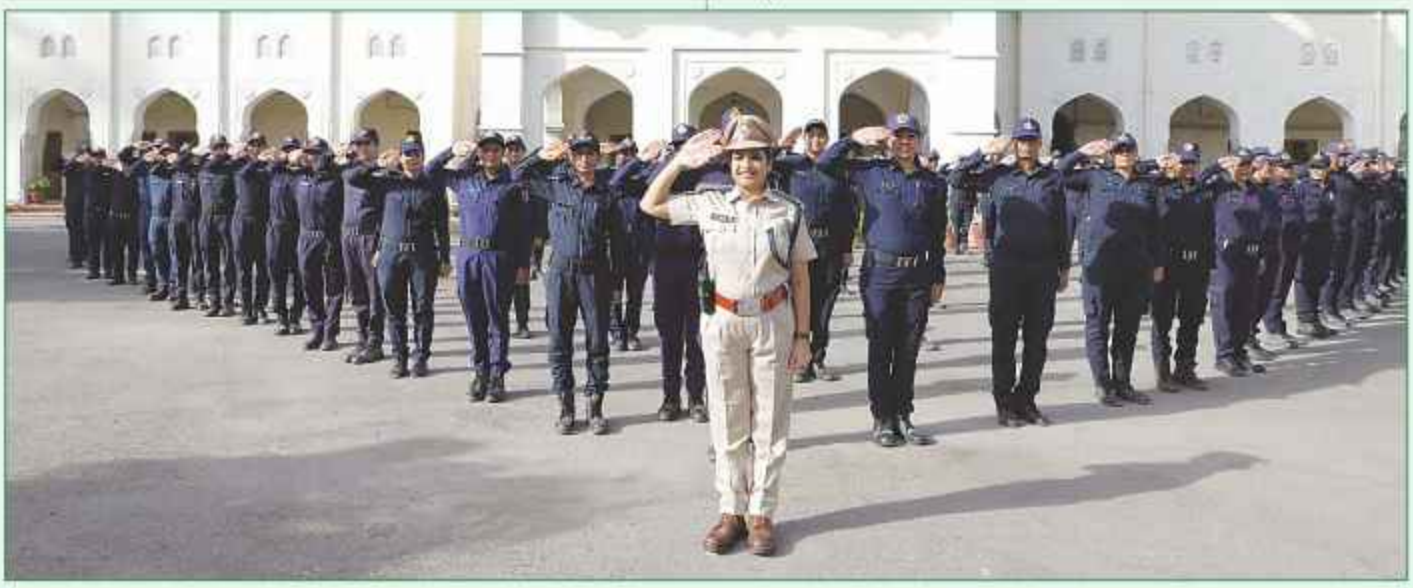

नववर्ष का उपहार, कम हुआ रसोई खर्च का भार

▪ सोनू शर्मा
▪ हेमेन्द्र सिंह
सहायक जनसम्पर्क अधिकारी

- **न्यूनतम दाम में रसोई गैस सिलेंडर के लिए राजस्थान देशभर में अग्रणी**
- **विकसित भारत संकल्प यात्रा में पीएम उज्ज्वला योजना के पंजीकरण में भी राजस्थान अव्वल**

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लक्ष्य को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अपना ध्येय माना है। इसी दिशा में प्रधानमंत्री श्री मोदी की गारंटी के तहत प्रदेश सरकार ने आम गृहणियों को मात्र 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने का संकल्प पत्र का अपना वायदा पूरा किया है। इससे प्रदेश की महिलाओं को धुएं से मुक्ति के साथ ही रसोई खर्च कम होने से उन परिवारों को आर्थिक सम्बल भी मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश की महिलाओं को नववर्ष का उपहार देते हुए 01 जनवरी 2024 से रसोई गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना प्रारम्भ की है। इस योजना के अन्तर्गत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एवं चयनित बीपीएल परिवारों को मात्र 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिल सकेगा। वर्तमान में राजस्थान देशभर में सबसे कम दाम में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने में अग्रणी है। प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 70 लाख से अधिक एवं 3 लाख 50 हजार से अधिक बीपीएल श्रेणी के रूप में पंजीकृत परिवार की महिलाओं को लाभ मिल सकेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मंशा है कि हकदारों को सीधे तौर पर लाभ सुनिश्चित हो, इसलिए राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही सब्सिडी की राशि सीधे ही लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित की जाएगी। इस योजना में पात्र लाभार्थियों को सालभर में कुल 12 सिलेंडर मिल सकेंगे।

पीएम उज्ज्वला योजना पंजीकरण में प्रदेश सिरमौर

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा की पहल की गई, जिसके माध्यम से केन्द्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ अंतिम पायदान तक सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में गरीब, युवा, महिला और किसान वर्ग को योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ मिले एवं कोई भी हकदार योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहे। जिससे वे स्वयं आत्मनिर्भर बनते हुए देश को विकसित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका निभाएं।

राजस्थान में 16 दिसम्बर 2023 से प्रारम्भ विकसित भारत संकल्प यात्रा में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के पंजीकरण में राजस्थान देशभर में अग्रणी है। प्रदेश में संचालित विकसित भारत संकल्प यात्रा में पीएम उज्ज्वला योजना में अभी तक 7.95 लाख से अधिक व्यक्तियों की ई-केवाईसी भी की गई है, इससे उन्हें भी रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना से लाभान्वित किया जा सकेगा। रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना की महिला लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा को रक्षा-सूत्र बांध कर आभार व्यक्त किया है।

धुएं की घुटन से मिली मुक्ति

श्रीमती कमलेश — श्रीमती मुन्नो देवी

विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में पहुंची श्रीमती मुन्नो देवी और श्रीमती कमलेश ने बताया घर में पहले चूल्हे पर लकड़ी जलाकर खाना पकाया जाता था, जिससे घर में धुआं हो जाने से घुटन व खांसी की समस्या, बच्चों के जलने का डर रहता था, परन्तु अब गैस कनेक्शन मिलने से उन्हें व उनके परिवार को फायदा पहुंचा है। इसके लिए सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद।

विकसित भारत-विकसित राजस्थान

लाइव प्रदर्शनों के माध्यम से आकर्षण बने ड्रोन

■ डॉ. आशीष खण्डेलवाल
उप निदेशक

विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान, कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सहित पूरे देश में इस तकनीक का लाइव प्रदर्शन किया गया। राजस्थान में 3 हजार से अधिक ड्रोन प्रदर्शन किए गए।

विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान ड्रोन एक प्रमुख आकर्षण बन गए। इन प्रदर्शनों में ड्रोन से उर्वरक छिड़काव, कीटनाशक छिड़काव, फसलों की निगरानी और अन्य कृषि कार्यों की जानकारी किसानों को मिली।

ड्रोन तकनीक का उपयोग करने से किसानों की दक्षता में काफी सुधार हो सकता है। ड्रोन का उपयोग कर उर्वरक और कीटनाशक का छिड़काव बहुत अधिक सटीकता के साथ किया जा सकता है। इससे भूमि और जल संसाधनों की बचत होती है और उत्पादकता में भी सुधार होता है। इसके अलावा, ड्रोन का उपयोग कर फसलों की निगरानी करना भी आसान हो जाता है। इससे किसानों को समय रहते फसलों की बीमारियों और कीटों की समस्याओं का पता चल सकता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं की भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया गया। महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिला किसान ड्रोन केंद्र की स्थापना कर महिला किसानों को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे महिला किसानों को कृषि में आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी।

ड्रोन दीदी : महिला स्वयं सहायता समूहों को उपलब्ध कराए जाएंगे ड्रोन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन प्रदान करने के लिए 1261 करोड़ रुपये के व्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र की योजना को मंजूरी दे चुका है। इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2023-24 से 2025-2026 की अवधि के दौरान किसानों को कृषि उद्देश्यों के लिए किराये की सेवाएं प्रदान करने के लिए 15,000 चयनित महिला एसएचजी को ड्रोन प्रदान करना है, जिनमें राजस्थान के महिला एसएचजी भी शामिल होंगे।

योजना की मुख्य विशेषताएं

- यह योजना कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और उर्वरक विभाग, महिला एसएचजी और प्रमुख उर्वरक कंपनियों के संसाधनों और प्रयासों से जुड़ी है।
- राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में चिन्हित समूहों में प्रगतिशील 15,000 महिला एसएचजी को ड्रोन प्रदान करने के लिए चुना जाएगा। साथ ही ड्रोन खरीदने के लिए महिला एसएचजी को ड्रोन और सहायक उपकरण पर खरीद शुल्क का 80 प्रतिशत अधिकतम आठ लाख रुपये तक की राशि केंद्रीय वित्तीय सहायता के रूप में दी जाएगी।
- एसएचजी के सीएलएफ राष्ट्रीय कृषि इन्फ्रा फाइनेंसिंग सुविधा के तहत ऋण के रूप में शेष राशि एकत्र कर सकते हैं। ऋण पर 3 प्रतिशत दर से ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी।
- महिला एसएचजी के सदस्यों में से चयनित एक को 15 दिवसीय प्रशिक्षण ड्रोन पायलट एवं पोषक तत्वों और कीटनाशकों के प्रयोग का 10 दिवसीय अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- एसएचजी के अन्य सदस्य व परिवार के सदस्य को ड्रोन तकनीशियन सहायक के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। ये प्रशिक्षण ड्रोन आपूर्ति के साथ एक पैकेज के रूप में रहेगा।
- ड्रोन द्वारा नैनो उर्वरकों जैसे नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के उपयोग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। एसएचजी छिड़काव के लिए किसानों को ड्रोन सेवाएं किराए पर देंगे।
- यह योजना किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए बेहतर दक्षता, फसल की पैदावार बढ़ाने और परिचालन की लागत को कम करने के लिए कृषि में उन्नत प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने में मदद करेगी।

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से हस्तशिल्पियों को मिल रहा संबल

■ विनय सोमपुरा
सहायक जनसम्पर्क अधिकारी

- 18 श्रेणी के हस्तशिल्पी करा सकते हैं योजना में पंजीयन
- औजार खरीद के लिए मिलेगा 15000 रुपये का ई-वाउचर
- बिना गारंटी मिल सकेगा सस्ता लोन

भारतवर्ष प्राचीन काल से ही हस्तशिल्प में समृद्ध रहा है। कालान्तर में कई हस्त कलाएं विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गईं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार का ध्येय सबका साथ-सबका विकास करते हुए आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करना है। इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के माध्यम से पीएम विश्वकर्मा योजना प्रारंभ की गई। यह योजना न केवल हस्त शिल्प से जुड़े विश्वकर्माओं को अपेक्षित सम्मान दिला रही है, अपितु हुनरमंदों के हौसले को भी नई उड़ान दे रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के माध्यम से इस योजना को जन-जन तक पहुंचाया जा रहा है तथा शिल्पियों का पंजीयन कर उन्हें विश्वकर्मा के रूप में नई पहचान दिलाई जा रही है। पूरे देश में अब तक लाखों हस्त शिल्पी इस योजना में लाभान्वित हो चुके हैं।

यह है पीएम विश्वकर्मा योजना

केंद्र सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के माध्यम से 17 सितम्बर 2023 को पीएम विश्वकर्मा योजना प्रारंभ की गई। योजना का उद्देश्य हाथ से अथवा औजार का उपयोग करके काम करने वाले पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को पहचानना और सशक्त बनाना है। प्रारंभिक तौर पर वर्ष 2027-28 तक के लिए लागू इस योजना के तहत 18 श्रेणी के हस्तशिल्पियों का पंजीयन कर उन्हें वित्तीय संबल तथा हस्त शिल्प के विपणन के अवसर प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

इनको मिल सकता है लाभ

योजना के तहत बढ़ई, नाव बनाने वाला, अस्त्रकार, लोहार, हथौड़ा, टूलकिट निर्माता, ताला बनाने वाला, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार (पत्थर तराशने वाला, पत्थर तोड़ने वाला), मोची (चर्मकार, जूता कारीगर), राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई, झाड़ू निर्माता, कॉयर बुनकर, गुड़िया और खिलौना निर्माता (पारंपरिक), नाई, माला निर्माता (मालाकार), धोबी, दर्जी तथा मछली पकड़ने का जाल निर्माता पात्र हैं।

यह है पात्रता

पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के कारीगर या शिल्पकार जो स्व-रोजगार के आधार पर असंगठित क्षेत्र में हाथों और औजारों से काम करते हैं, पात्र हैं। लाभार्थी ने स्व-रोजगार या व्यवसाय विकास के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा पिछले 5 वर्षों में चलाई जा रही क्रेडिट-आधारित योजनाओं जैसे पीएमईजीपी, पीएम स्वनिधि, मुद्रा आदि के तहत ऋण नहीं लिया हो। हालांकि मुद्रा और स्वनिधि के लाभार्थी जिन्होंने अपना ऋण चुका दिया है, वे पीएम विश्वकर्मा के तहत पात्र होंगे। 5 वर्ष की अवधि की गणना ऋण स्वीकृत होने की तिथि से की जाएगी। योजना के तहत पंजीकरण और लाभ परिवार के एक सदस्य तक ही सीमित रहेगा।

यह है प्रक्रिया

पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ने के लिए पात्र व्यक्ति को अपने

नजदीकी सामान्य सेवा केंद्र यथा अटल सेवा केंद्र, ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा। इसके लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक विवरण, राशन कार्ड की आवश्यकता रहेगी। पंजीयन पूर्णतया निःशुल्क है। पंजीयन के पश्चात शहरी क्षेत्र में नगर निकाय के अधिशासी अधिकारी तथा ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच की ओर से आवेदनों का ऑनलाइन सत्यापन किया जाता है।

इसके बाद आवेदन अग्रिम कार्यवाही के लिए जिला कलक्टर स्तर पर प्रेषित किए जाते हैं। जिला स्तरीय कमेटी की ओर से सत्यापित किए जाने के पश्चात आवेदन को विश्वकर्मा के रूप में प्रमाण-पत्र तथा आईडी कार्ड जारी किए जा रहे हैं।

यह है लाभ

योजना में पंजीयन कराने पर संबंधित हस्तशिल्पी को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण-पत्र और पहचान-पत्र जारी किया जाता है। इससे आवेदक को विश्वकर्मा के रूप में पहचान मिलती है। आवेदक को 5 दिन की बेसिक ट्रेनिंग तथा 15 दिन या इससे अधिक का कौशल उन्नयन प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन 500 रुपये भत्ता भी देय है। आवेदक को अपने व्यवसाय के लिए उन्नत उपकरण खरीदने 15 हजार रुपये की सहायता ई-आरयूपीआई अथवा ई-वाउचर के रूप में प्रदान की जाती है। इसके अलावा बिना जमानत के पहली किस्त के रूप में मात्र 5 प्रतिशत ब्याज दर पर 1 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

राजस्थान में अब तक डेढ़ लाख से अधिक आवेदन

राजस्थान हस्त कलाओं के लिए विख्यात है। प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में विभिन्न जाति के लोग अपने पुरखों की कला को जीवित रखे हुए हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना इन सभी हस्तशिल्पियों के लिए वरदान साबित हो रही है। योजना को लेकर प्रदेश में खासा रूझान है। 11 जनवरी 2024 तक इस योजना में डेढ़ लाख से अधिक आवेदन हो चुके हैं, जिनके सत्यापन सहित अग्रणी कार्यवाही प्रगतिरत हैं। योजना के प्रति हस्त शिल्पियों के रूझान को देखते हुए राज्य सरकार ने आवेदनों के त्वरित सत्यापन के लिए सभी ग्राम पंचायतों के सरपंचों को पोर्टल से जोड़ने के लिए विशेष मुहिम चला रखी है।

- श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेण्डर्स को वृद्धावस्था में भी संबल प्रदान करने 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू की है। इस योजना में 60 से 100 रूपए मासिक प्रीमियम देने पर 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर प्रतिमाह 2 हजार रूपए पेंशन प्राप्त हो सकेगी। प्रतिमाह प्रति व्यक्ति करीब 400 रुपये का प्रीमियम राज्य सरकार की ओर से वहन किया जायेगा।

विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना

राज्य सरकार की ओर से लागू विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के तहत विभिन्न वर्गों के हस्तशिल्पियों को टूलकिट क्रय करने के लिए 5000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। उक्त योजना में उद्योग विभाग अथवा विकास आयुक्त या हस्तशिल्प (भारत सरकार) द्वारा पहचान पत्र धारी 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे हस्तशिल्प जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है वे एसएसओ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव-2024

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से हस्तशिल्पियों के विकास का मार्ग प्रशस्त

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव-2024 के उद्घाटन अवसर पर जोधपुर में कहा कि प्राचीन काल से ही लघु उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन से लघु उद्यमी आत्मनिर्भर बन रहे हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से हस्तशिल्प जैसी कलाओं और लघु उद्योगों से जुड़े उद्यमियों का विकास मार्ग प्रशस्त हुआ है। इससे हस्तशिल्पियों को आर्थिक सम्बल मिलने के साथ-साथ उनकी प्रगति के अवसर सृजित हुए हैं।

श्री शर्मा ने उद्यमियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान को नई गति प्रदान करने के लिए सरकार भरसक प्रयास कर रही है। इस क्षेत्र में निरंतर कार्य करते हुए ऊर्जा क्षेत्र में राज्य को आत्मनिर्भर बनाएंगे।

क्षुधाहारी, भोजन गुणकारी

श्री अन्नपूर्णा रसोई

▪ अभय सिंह
सहायक जनसम्पर्क अधिकारी

प्रदेश में हर जरूरतमंद को समय पर पौष्टिक, पर्याप्त और ससम्मान भोजन मिले इसके लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा 6 जनवरी 2024 को धन धान्य की अधिष्ठात्री देवी मां अन्नपूर्णा के नाम पर "श्री अन्नपूर्णा रसोई" में लाभार्थियों को परोसी जाने वाली थाली में मात्रात्मक वृद्धि किए जाने पर अब 600 ग्राम भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है।

योजना के अन्तर्गत इन रसोइयों में सभी आय वर्ग के लोगों, विद्यार्थियों, श्रमिकों एवं सभी जरूरतमंदों को मात्र 8 रुपए में गुणवत्तायुक्त भोजन मिल रहा है। अन्य जिलों में प्रवास एवं शहर-कस्बों में कामकाज के दौरान भी शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन की उपलब्धता श्री अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से सुनिश्चित होती है। लाभार्थियों को परोसी जाने वाली थाली में 600 ग्राम भोजन भोजन मेन्यू में गुणात्मक सुधार करते हुए 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम चावल या मिलेट्स (श्रीअन्न) खिचड़ी और अचार दिया जा रहा है।

श्रीअन्न के समावेशन बढ़ा पोषण

भारत सरकार ने मोटे अनाजों को बढ़ावा देकर आमजन की थाली में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए "श्रीअन्न योजना" का शुभारंभ किया है। इसी से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार ने भी श्री अन्नपूर्णा रसोई में परोसी जाने वाली थाली में 100 ग्राम मोटे अनाजों से निर्मित खिचड़ी को शामिल किया है।

अनुदान बढ़ाकर किया 22 रुपये

योजनांतर्गत लाभार्थी को 8 रुपये में शुद्ध, ताजा एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जाता है और सम्मानपूर्वक एक स्थान पर बैठकर भोजन करने की उत्तम व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार द्वारा 17 रुपये प्रति थाली अनुदान को बढ़ाकर 22 रुपये किया गया है। भोजन की गुणवत्ता के साथ किसी तरह का समझौता न हो, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक रसोई की रीयल टाइम ऑनलाइन मॉनिटरिंग की व्यवस्था है। एसएमएस द्वारा योजना के लाभार्थियों से भी फीडबैक लिया जाता है। प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए राज्य एवं जिला स्तरीय समिति भी परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता जांचती है।

योजना में जनसहभागिता

श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में कोई भी व्यक्ति या संस्था और औद्योगिक व्यापारिक संस्थान सीएसआर मद से सहयोग कर एक या अधिक रसोई के संपूर्ण संचालन का उत्तरदायित्व ले सकते हैं। वर्षगांठ, जन्मदिवस या अन्य अवसर पर एक या दोनों समय का भोजन प्रायोजित किया जा सकता है। आगुंतकों के लिए प्रायोजित भोजन प्रायोजित सीमा तक निःशुल्क उपलब्ध रहेगा। प्रायोजक व्यक्ति या संस्था को लागत राशि का भुगतान संबंधित बैंक खाते में करना होता है। प्रायोजक का नाम एवं अवसर के कारण का उल्लेख डिस्प्ले बोर्ड पर किया जाता है।

योजना का संचालन

नगरीय क्षेत्रों में रसोइयों का संचालन स्वायत्त शासन विभाग के अधीन नगरीय निकायों द्वारा किया जाता है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रसोइयों संचालन पंचायतीराज विभाग के अधीन संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। वर्तमान में नगरीय क्षेत्रों में 1000 व ग्रामीण क्षेत्रों में 942 श्री अन्नपूर्णा रसोइयों का संचालन किया जा रहा है। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के हेल्पलाइन नंबर 181 के माध्यम से भोजन की गुणवत्ता या योजना से जुड़े दूसरे पहलुओं से सम्बन्धित सुझाव या शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

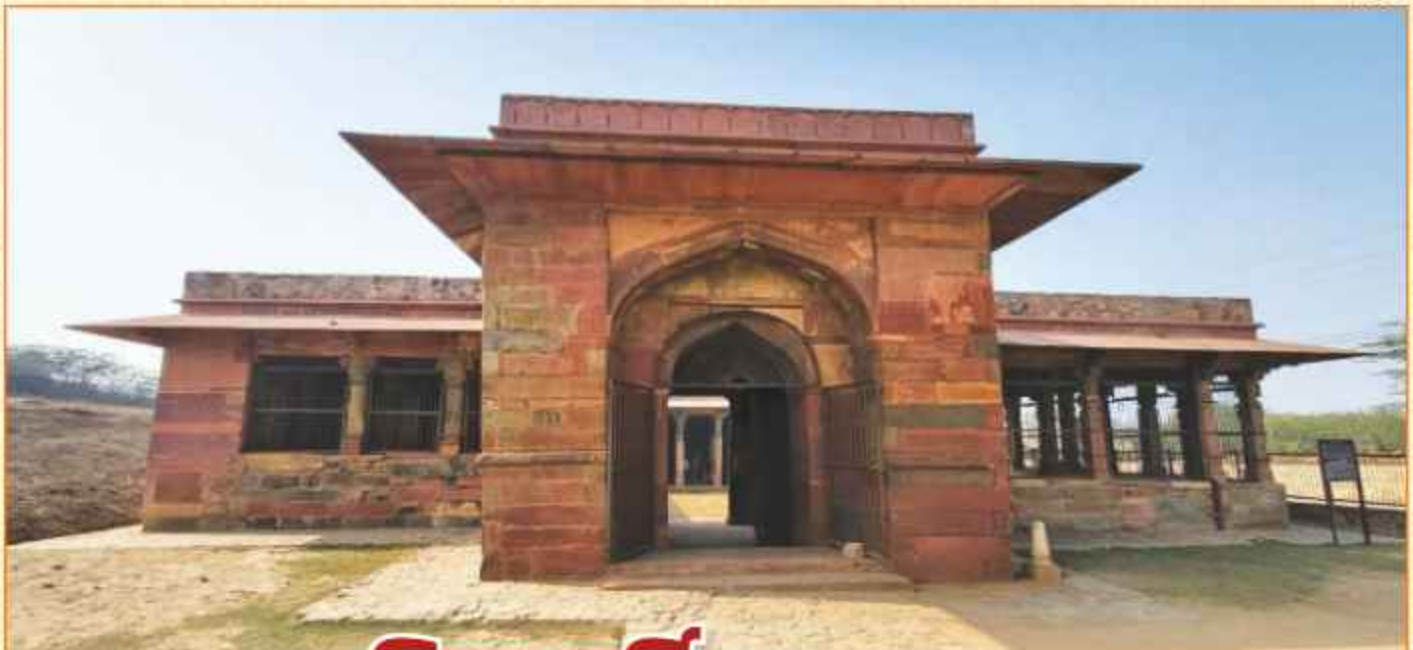

बिना मूर्ति का पौराणिक विष्णु मंदिर

कामां स्थित चौरासी खम्भा मंदिर को पुराणों में विष्णु मंदिर बताया गया है। वर्तमान डीग जिले में स्थित राजस्थान का यह हिस्सा योगेश्वर श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली ब्रज क्षेत्र में पड़ता है। कामां पर सूरसेन का शासन रहा है। आक्रांताओं ने इस पुरातन मंदिर को तोड़कर अपना धार्मिक स्थल बनाने का असफल प्रयास किया।

आज का यह चौरासी खम्भा मंदिर बिना मूर्ति का है जिसे पुराणों में विष्णु मंदिर कहा गया था। आक्रांताओं ने इस नवग्रह आधारित विष्णु मंदिर की मूर्तियों को चुरा लिया था। आज भी मंदिर के खम्भों पर नवग्रह, विष्णु अवतार एवं शिव पार्वती के विवाह की आकृतियां गढ़ीं हुईं हैं। इस मन्दिर की एक विशेषता यह भी है कि कोई भी आज तक इसके खंभों की सही गिनती करने में कामयाब नही हुआ है। गणना करने पर कभी ये खम्भे 84 से ज्यादा तो कभी कम निकलते हैं।

गोपाल गुप्ता
वरिष्ठ पत्रकार

Postal Regd. No. Jaipur City/413/2023-25
Registered with Registrar of Newspapers for India under R. No. 56175/1991

राजस्थान सुजस का यह अंक
https://dipr.rajasthan.gov.in/pages/sm/government-order/attachments/134/85/10/1702
पर देखा जा सकता है।

#DIPRRajasthan

प्रकाशक व मुद्रक — सूचना एवं जनसंपर्क आयुक्त, सुनील शर्मा द्वारा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के लिए, सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) से प्रकाशित
संपादक— श्रीमती अलका सक्सेना, मैसर्स कृष्णा प्रिन्टर्स, डी—14, सुदर्शनपुरा, जयपुर से मुद्रित, 'राजस्थान सुजस' पृष्ठ संख्या 60, लागत मूल्य 33.30 रुपये • 30,000 प्रतियां